



प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ उपहार अमृतफल आंवला

आंवले की एक डाली पर पत्ते एवं प्रथमेश डंपर, यह करीब 20 फीट से 25 फुट तक लंबा झारीय पौधा होता है। यह पशुधारा के अलावा यूरॉप और अफ्रीका में भी पाया जाता है। हिमालयी क्षेत्र और प्राद्वीपीय भारत में आंवला के पौधे बहुतायत मिलते हैं। इसके फूल घंटे की तरह होते हैं। इसके फल सामान्यरूप से छोटे होते हैं, लेकिन प्रसंस्कृत पौधे में थोड़े बड़े फल लगते हैं। इसके फल हरे, चिकने और गुदेदार होते हैं। स्वाद में इनके फल कसयाय होते हैं। ज्यादातर खट्टापन कटारे में पाया जाता है। संस्कृत में इसे अमृता, अमृतफल, आमलकी, पंचरसा इत्यादि, अंग्रेजी में 'एंब्लिक माइरीबालन' या इण्डियन गुजबेरी तथा लैटिन में 'फिल्लैथस एंबेलिका' (Phyllanthus emblica) कहते हैं। यह वृक्ष समस्त भारत में जंगलों तथा बाग-बगीचों में होता है। इसकी ऊँचाई 20 से 25 फुट तक, छाल राख के रंग की, पत्ते इमली के पत्तों जैसे, किंतु कुछ बड़े तथा फूल पीले रंग के छोटे-छोटे होते हैं। फूलों के स्थान पर गोल, चमकते हुए, पकने पर लाल रंग के, फल लगते हैं, जो आंवला नाम से ही जाने जाते हैं। वाराणसी का आंवला सब से अच्छा माना जाता है। यह वृक्ष कार्तिक में फलता है।



(अवस्था को बनाए रखनेवाला) तथा धात्री (माता के समान रक्षा करनेवाला) कहा है। इसका प्रयोग किसी भी रूप में किया जाय इसके गुणों में कोई कमी नहीं आती है। प्राचीन काल से ही इसे सर्वगुण सम्पन्न फल माना जाता रहा है। विटामिन और भी कई रासायनिक गुणों से समृद्ध ये फल सर्दियों में खासकर उपलब्ध होता है। अचार, सब्जी, छुट्टा, मुर्खा व सुपारी के रूप में विभिन्न प्रकार से इसका उपयोग हम किया करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी हमने बना ली र आंवला कैडीर. बिल्कुल सादा

और सरल तरीके से. एक किलो ताजा रसीला आंवला लेकर उन्हें एक दिन के लिए पानी में भिगोकर रखें और दूसरे दिन आंवला को अच्छी तरह से धोकर स्टीम में 12-15 मिनट तक मध्यम आंच पर भाप से पका लें. बाद में स्टीम से निकालकर उन्हें हल्का सा ठंडा होने दें और उनकी फांके निकालकर गुठलियों को अलग कर लें. आंवला की फांकों को एक गहरे बर्तन में लेकर उन पर एक इंच ऊपर तक चीनी भर लें और ढक्कन लगाकर रख दें. एक दिन बाद आप देखेंगे कि चीनी पूरी तरह घुलकर रस बन गई है और आंवले ऊपर तैर रहे हैं, तो आप इस मिश्रण को एक साफ चम्मच से अच्छी तरह हिलाकर वापस ढक्कन 2-3 दिन के लिए रख दें, ध्यान रखें कि इसे दिन में एक दो बार चम्मच से चलाते रहें, ताकि फफूंद नही लगे.

दो दिन के बाद आप देखेंगे कि आंवले रस से भरकर नीचे डूब गए हैं. इसे एक दिन के लिए और रखकर आंवलों को रस में से निकालकर एक बड़े थाल में फैलाकर धूप में रखें. दिनभर की तेज धूप से इसका रस सूख जाता है. बाद में इन सूखे हुए आंवलों को एक बर्तन में रखकर उन पर पिसी हुई चीनी, कालीमिर्च पाउडर और पिसा हुआ काला नमक डालकर अच्छी तरह से चलाएँ ताकि सभी आंवलों पर कोटिंग हो जाये. बाद में इस चटपटी जायकेदार स्वास्थवर्धक आंवला कैडी को एक साफ कांच के मर्तबा में भरकर रख दें और फिर इसे अपनी सुविधानुसार खाने का आनंद लें. 1.

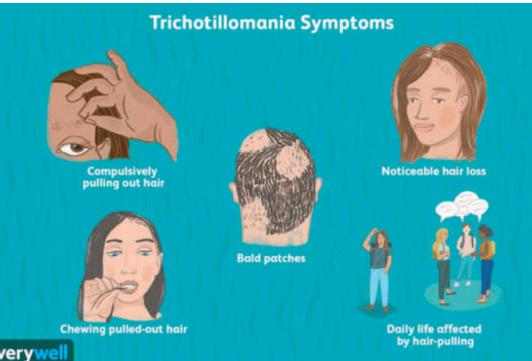
क्या है Trichotillomania

Trichotillomania एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी ही भौहों, पलकें, सिर के बाल, दाढ़ी या शरीर के अन्य हिस्सों के बाल बार-बार और अनियंत्रित रूप से उखाड़ता है। इससे खाली पैच, दुख, अपराधबोध और चिंता जैसी समस्याएँ हो सकती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका इलाज संभव है।

क्या होता है Trichotillomania? यह एक Impulse Control Disorder है, यानी व्यक्ति को बाल उखाड़ने की तीव्र इच्छा आती है और वह उसे रोक नहीं पाता। कई बार व्यक्ति बिना जाने, किसी तनाव, चिंता, बोरियत या भावनात्मक परेशानी में भी बाल उखाड़ने लगता है।

मुख्य लक्षण

1. सिर, भौहों या पलकों के बाल बार-बार उखाड़ना
2. बाल उखाड़ने के बाद मन को थोड़ी राहत या संतोष
3. स्काल्प/भौहों में खाली पैच बनना
4. बालों को उंगलियों से घुमाना, खींचना या मुंह में डालना
5. इस आदत को छुपाने की कोशिश करना



क्यों होता है? (कारण)

Trichotillomania का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि कई कारकों का मिश्रण हो सकता है:

1. Stress या Anxiety
2. Depression
3. Habit-based behavior जो समय से मजबूत हो जाती है
4. Genetic tendency (परिवार में किसी को हो तो जोखिम अधिक)
5. दिमाग के habit circuit में बदलाव

इलाज के प्रभावी तरीके अच्छी खबर यह है कि यह पूरी तरह काबू में लाया जा सकता है।

1. Habit Reversal Therapy (HRT) – सबसे प्रभावी इलाज इसमें व्यक्ति को
 1. ट्रिगर पहचानना
 2. बाल उखाड़ने के बदले कोई दूसरी harmless activity (जैसे रबर बैंड खींचना, बॉल दबाना) अपनाना

3. व्यवहार को बदलना सिखाया जाता है।
2. Cognitive Behaviour Therapy (CBT) तनाव और चिंता को कम करने तथा आदत को समझकर उसे बदलने में मदद करता है।
3. चिकित्सा / दवाएँ कभी-कभी डॉक्टर
 1. SSRIs (anxiety/depression के लिए)
 2. N-Acetylcysteine (NAC) जैसी दवाएँ सुझाते हैं। (दवाएँ हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही)
 4. Self-help उपाय
 1. हाथों को किसी activity में व्यस्त रखना
 2. तनाव कम करने की तकनीकें – योग, ध्यान, गहरी सांस
 3. सिर या भौहों पर ढीली टोपी/कवर
 4. ध्यान भटकाने के तरीके

क्या Trichotillomania ठीक हो सकता है? हाँ, बहुत से लोग थैरेपी + self-control techniques से पूरी तरह ठीक हो जाते हैं या काफी सुधार देखते हैं। शुरुआत जितनी जल्दी होती है, परिणाम उतने बेहतर होते हैं।

मस्तिष्क में यादें कहाँ संग्रहीत होती हैं?

आधुनिक विज्ञान की स्पष्ट और प्रभावशाली व्याख्या

मानव मस्तिष्क में स्मृति एक ही जगह पर संग्रहीत नहीं होती। स्मृति एक वितरित (distributed) प्रणाली है — यानी अलग-अलग प्रकार की यादें मस्तिष्क के अलग-अलग हिस्सों में बंती, सहेजी और पुनः प्राप्त की जाती हैं। सामान्य रूप से, स्मृति दो मुख्य प्रकार की होती है:

1. स्पष्ट स्मृति (Explicit / Conscious Memory) – जिसे हम जान-बूझकर याद करते हैं
2. अस्पष्ट स्मृति (Implicit / Unconscious Memory) – कौशल, आदतें, मोटर-स्किल, जिनके बारे में हमें सोचने की आवश्यकता नहीं होती

स्पष्ट स्मृति के लिए तीन प्रमुख मस्तिष्क भाग हैं:

1. हिप्पोकैम्पस
2. नियो-कोर्टेक्स
3. अमिगडाला

जबकि कौशल आधारित स्मृति के लिए:

4. बेसल गैंग्लिया और सेरेबेलम

1. हिप्पोकैम्पस – नई यादों का निर्माता और व्यवस्थित करने वाला केंद्र, हिप्पोकैम्पस मस्तिष्क के टेम्पोरल लोब में स्थित होता है। यह नई एपिसोडिक यादों (व्यक्तिगत अनुभवों) को बनाता, व्यवस्थित करता और अल्पकालिक स्मृति को दीर्घकालिक स्मृति में बदलने में मदद करता है।

हिप्पोकैम्पस क्या करता है?

1. नई यादें बनाता
2. "कहाँ-क्या-कैसे हुआ" वाली घटनाओं को व्यवस्थित करता
3. अल्पकालिक स्मृति को दीर्घकालिक स्मृति में बदलता
4. रास्ते, स्थान और दिशाएँ याद रखने में

मदद करता

5. H.M. का प्रसिद्ध केस- 1953 में एक मरीज, हेनरी मोलाएसन (H.M.), के हिप्पोकैम्पस को मिर्गी (epilepsy) के इलाज के लिए हटाया गया। परिणाम:
 1. मिर्गी ठीक हो गई
 2. बुद्धि सामान्य रही
 3. लेकिन वह नई यादें नहीं बना पाए
 4. केवल कुछ मिनटों की स्मृति रह पाती थी
 5. पुरानी यादें सुरक्षित रहीं
 6. आश्चर्यजनक रूप से, वे नए मोटर स्किल सीख सकते थे (जैसे ड्राइंग, पजल)

लेकिन उन्हें यह याद नहीं रहता कि उन्होंने ये कौशल सीखे हैं

इस घटना से क्या पता चला? हिप्पोकैम्पस नई यादें बनाने के लिए आवश्यक है, लेकिन स्थायी स्मृति का भंडार नहीं है। अलग-अलग प्रकार की यादें मस्तिष्क के अलग-अलग नेटवर्क में संग्रहीत होती हैं

2. नियो-कोर्टेक्स – दीर्घकालिक स्मृति का विशाल भंडार नियो-कोर्टेक्स (cerebral cortex) मस्तिष्क की बाहरी परत है, जिसमें समय के साथ यादें स्थायी रूप से जमा हो जाती हैं।

नियो-कोर्टेक्स को भूमिका

1. दीर्घकालिक स्मृति का संग्रह
2. जानकारी, तथ्य, भाषा, ज्ञान की याद
3. पुरानी एपिसोडिक और अनुभव आधारित यादें
4. ध्वनि, दृश्य, स्पर्श आदि की अलग-अलग स्मृतियों को सहेजना
5. नवीनतम वैज्ञानिक जानकारी

एक ही स्मृति मस्तिष्क के कई हिस्सों में "टुकड़ों" में संग्रहीत होती है

7. नंद (विशेषकर गहरी नंद) के दौरान हिप्पोकैम्पस यादों को नियो-कोर्टेक्स में

"स्थानांतरित" करता है

8. इसे System Consolidation कहते हैं यही कारण है कि अच्छी नंद याददास्त को मजबूत करती है।
3. अमिगडाला – भावनाओं से जुड़ी स्मृति का केंद्र अमिगडाला छोटी बादाम-आकार की संरचना है जो भावनात्मक यादों को संभालती है। अमिगडाला क्या करता है?
 1. डर, खुशी, क्रोध, तनाव, सुरक्षा, खतरा — इनसे जुड़ी यादें मजबूत बनाता है
 2. यादों को भावनाओं के साथ जोड़कर उन्हें "ज्यादा जीवंत" बनाता है

इसके प्रभाव दुर्घटना, सफलता, अपमान, तनाव — ऐसी घटनाएँ जीवन भर याद रहती हैं। PTSD जैसी बीमारियों में अमिगडाला का ओवर-एक्टिव होना पाया जाता है

4. बेसल गैंग्लिया और सेरेबेलम – कौशल और आदतों की स्मृति यह भाग अस्पष्ट (implicit) या कौशल आधारित स्मृति को संभालते हैं।

ये कौन-सी यादें हैं?

- 1। साइकिल चलाना
- तैरना
- टाइपिंग
- संगीत वाद्य बजाना
- रोजमर्रा की आदतें

ये वह स्मृतियाँ हैं जिन्हें हम सोचकर नहीं बल्कि आदत के बल पर करते हैं। H.M. जैसे मरीज मोटर स्किल सीख सकते थे क्योंकि यह स्मृति हिप्पोकैम्पस पर निर्भर नहीं है।

नवीनतम वैज्ञानिक विकास (2022-2025)

1. स्मृति एंग्राम (Memory Engrams) की पहचान अब यह साबित हो चुका है कि हर स्मृति विशिष्ट न्यूरॉन्स के नेटवर्क में बंती है।
1. विज्ञान इन नेटवर्क को

सक्रिय/निष्क्रिय कर सकता है।

2. भूल चुकी यादें पुनः सक्रिय करना।
3. डरपंती यादों के भाव बदलना (जैसे आतंक → शांति)
4. शुरुआती अल्जाइमर में यादों की पुनर्स्थापना
2. नंद के दौरान स्मृति-रीप्ले हिप्पोकैम्पस नंद में "भूती" की तरह दिनभर की घटनाएँ रिप्ले करता है और उन्हें मजबूती से कोर्टेक्स में जमा करता है।
3. डीप ब्रेन स्टिमुलेशन अल्जाइमर और गंभीर स्मृति-हानि वाले मरीजों में याददास्त सुधारने के लिए नई तकनीकों पर शोध चल रहा है।
4. मस्तिष्क स्मृति को "होलोग्राम" की तरह संग्रहीत करता है

याद एक जगह नहीं, बल्कि पूरे मस्तिष्क के नेटवर्क में बंती होती है इसलिए कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त होने पर भी कई यादें बची रहती हैं।

5. जीवनभर नई न्यूरॉन्स बनाना हिप्पोकैम्पस में वयस्क में भी नए न्यूरॉन्स बनते हैं। इसे Neurogenesis कहते हैं। यह सीखने और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

संशोधन सार (Impressive Summary)

1. हिप्पोकैम्पस नई यादें बनाता और व्यवस्थित करता है
2. नियो-कोर्टेक्स पुरानी और दीर्घकालिक यादों को संग्रहीत करता है
3. अमिगडाला भावनात्मक यादों को मजबूत बनाता है
4. बेसल गैंग्लिया और सेरेबेलम कौशल, आदत और मोटर स्किल को सहेजते हैं

आधुनिक विज्ञान साबित करता है कि नेटवर्क में बंती है।

1. विज्ञान इन नेटवर्क को

60+ उम्र वालों के लिए किडनी बचाने की जरूरी सावधानियाँ...

1. पानी पिएँ, लेकिन समझदारी से, दिन भर में थोड़ा-थोड़ा पानी पिएँ। रोजाना 1.5-2 लीटर पर्याप्त है (अगर डॉक्टर ने प्रतिबंध न लगाया हो)। शाम 7 बजे के बाद ज्यादा पानी न पिएँ ताकि रात में बार-बार बाथरूम न जाना पड़े। ध्यान रखें सुबह का पेशाब हल्का पीला होना चाहिए — बहुत गहरा रंग dehydration का संकेत है। ध्यान रखें: बहुत ज्यादा नींबू पानी, जूस या हर्बल टी भी किडनी पर लोड डाल सकते हैं।

2. ब्लड प्रेशर नियंत्रण — 60+ के लिए सबसे जरूरी घर पर हफ्ते में 2 बार BP चेक करें। आदर्श BP: 120-129 / 70-80 (डॉक्टर की सलाह अनुसार)। हाई BP चुपचाप किडनी को नष्ट करता है।

क्या करें:

1. नमक कम करें, पापड़/अचार/नमकीन से दूरी।
2. रोज 30 मिनट टहलें।
3. 7 घंटे नींद लें।

3. दवाइयों का सावधानी से इस्तेमाल 60+ में लोग अक्सर कई दवाइयों लेते हैं — ये किडनी पर ज्यादा भार डालती हैं। इन दर्दनाशकों का नियमित उपयोग न करें:

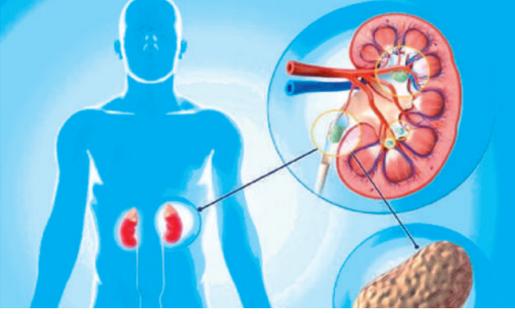
1. Ibuprofen
- Diclofenac
- Naproxen

दर्द वाले स्प्रे/बाम/जिम में NSAIDs हों सप्लिमेंट्स भी लिमिट में लें:

1. ज्यादा Vitamin C → स्टोन बनाता है
2. ज्यादा Vitamin D → कैल्शियम बढ़ाकर किडनी को नुकसान
3. Calcium गोलीयाँ बिना कारण न लें
4. अनजाने हर्बल पाउडर न लें

नियम: "दो से ज्यादा दवाएँ ले रहे हों, तो डॉक्टर से पूछें — क्या इनमें किडनी पर असर है?"

4. डायबिटीज कंट्रोल (अगर है) 60+ उम्र में डायबिटीज किडनी को सबसे तेज नुकसान पहुँचाती है।



लक्ष्य:

1. Fasting sugar <100-110 mg/dl
2. HbA1c <6.5-7%

साल में एक बार जरूर करवाएँ:

1. Urine microalbumin
2. Creatinine + eGFR
3. नमकीन, चिप्स, पापड़
4. अचार
5. सोडा, पैकड स्नैक्स
6. प्रोसेस्ड चीज, प्रोसेस्ड मीट

बढ़ने पर किडनी की फिल्टरिंग क्षमता इनसे बचें:

1. बिस्किट, केक, ब्रेड
2. इस्टेट नूडल्स, इस्टेट सूप
3. नमकीन, चिप्स, पापड़
4. अचार
5. सोडा, पैकड स्नैक्स
6. प्रोसेस्ड चीज, प्रोसेस्ड मीट

नमक कम, जड़ी-बूटियाँ ज्यादा: हल्दी, कालीमिर्च, रोजमरी, राई, जीरा।

6. गट हेल्थ सही रखें 60+ में पाचन धीमा हो जाता है, जिससे सूजन बढ़ती है और किडनी पर असर होता है।

रोज खाएँ:

1. एक कटोरी दही/योगर्ट
2. दो तरह की सब्जियाँ
3. छिलके वाला फल (सेब/नाशपाती)
4. भिगोए हुए बादाम/अलसी/कद्दू के बीज

इनसे बचें:

1. बार-बार एंटीबायोटिक

5 आदतें जो चुपचाप किडनी को नुकसान पहुँचाती हैं



1. पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) प्यास लगना देर से मिलने वाला संकेत है।

- A. सुबह बढ़ा गिलास पानी जरूर पिएँ, चाहे तो नींबू, अदरक, रोजमरी मिलाएँ।
- B. रोज का पानी: वजन (किलो) × 30 = ml.
- C. 75% पानी शाम 5 बजे से पहले।

साफ पेशाब = अच्छा हाइड्रेशन।

2. छुपा हुआ सोडियम ब्रेड, नमकीन, इस्टेट नूडल्स, सूप, सॉसेज, स्नेक्स, सोडा, कुकीज आदि में बहुत सोडियम होता है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और किडनी जल्दी खराब होती है।

नियम:

- अ. कम पैकड फूड्स, ज्यादा प्राकृतिक।
- ब. पोटेशियम/मैग्नीशियम बढ़ाएँ:

3. दवाइयों और सप्लिमेंट्स का ज्यादा उपयोग रोज-रोज दर्द की गोलीयाँ (ibuprofen, diclofenac, naproxen) किडनी को नुकसान करती हैं। ज्यादा Vitamin C → स्टोन; ज्यादा Vitamin D → कैल्शियम बढ़कर किडनी को जहरीला कर सकता है। दवा/सप्लिमेंट हमेशा डॉक्टर की सलाह से लें।

4. चेक-अप को नजर अंदाज करना ("में ठीक हूँ तो मैं स्वस्थ हूँ") किडनी को गुरु रूप से बिल्कुल चुप रहता है। 1. साल में 2 बार — यूरिन टेस्ट + क्रिएटिनिन टेस्ट जरूर करवाएँ। 2. ब्लड प्रेशर नियमित चेक करें — यह बिना लक्षण के किडनी को खराब करता है।

5. खराब गट हेल्थ बिगड़ा माइक्रोबायोम सूजन पैदा करता है → डायबिटीज, हार्ट रोग, किडनी डैमेज तक।

रोज खाएँ: दही, कंबुचा, केफिर, सब्जियाँ, छिलके वाले फल, दालें, बीज।

इनसे बचें जंक, ज्यादा नमक, बेवजह एंटीबायोटिक से बचें।

किडनी मरीजों के लिए खतरनाक फल: स्टार फ्रूट (केरेम्बोला) इसमें ऑक्सालेट और caramboxin नामक टॉक्सिन होता है। किडनी फेलियर वालों के लिए बहुत खतरनाक — उल्टी, झटके, भ्रम, और इमरजेंसी डायलिसिस तक की नौबत ला सकता है। स्वस्थ लोग भी इसे कभी-कभी ही खाएँ, अधिक मात्रा या जूस के रूप में नहीं।

पुनर्नवा — फिर से नया कर दे तन-मन की धरा

आयुर्वेद की कोमल गोद से निकली यह जड़ी-बूटी नाम ही बताता है — जीवन को पुनः नया बनाना। भीतर छिपी थकान, सूजन, अवसाद, सबको धीरे-धीरे दूर भगाना। किडनी के लिए संजीवनी-सी, पेशाब की जलन, रुकावट, सूजन में राहत लाएँ। लीवर को दे स्वच्छ उजाला, पीलिया, संक्रमण, फेटी लिवर को सहज ठीक कर जाएँ। हार्मोनल संतुलन का कोमल स्पर्श, कमजोरी, एनीमिया, मासिक समस्या में सहारा दें। शुगर हो या बढ़ा रक्तचाप, धीरज से नियंत्रण का थोड़ा रास्ता दें। त्वचा पर भी इसका आशीर्वाद, फोड़े, फुंसी, एक्जिमा में मधुर उपचार। वजन घटाने में भी सहायक, शरीर से

विषैले तत्व कर दे पार। सेवन सरल —

1. चूर्ण 1-3 ग्राम भोजन बाद या पुनर्नवादिष्ट दिन में दो बार।
2. सब्जी रूप में साग भी उत्तम, स्वाद के संग स्वास्थ्य का उपहार।

ध्यान रहे — गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएँ केवल चिकित्सक सलाह के बाद सेवन करें। पुनर्नवा है प्रकृति की कोमल पुकार - नियमित लो, संयम से लो और जीवन को फिर से नया आकार दो।

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मौलिक कारणों को समझे बिना निदान बेहद मुश्किल, समझिए हजूर!

कमलेश पाण्डेय

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ता वायु प्रदूषण अब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के गले ही हड्डी बन चुकी है क्योंकि उनके मातहत कार्यरत प्रशासन निरंतर अदृशदृष्टिता केरल का याव निर्णय लेने का आदी बन चुका है। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की चिंताएं स्वाभाविक हैं, लेकिन इन्हें भी प्रदूषण की बुनियादी बातों को समझना पड़ेगा और सर्वमन्या हल देने पड़ेंगे अन्यथा बात का बतंगड़ बनते देर नहीं लगेगी।

इसलिए सबसे पहले दिल्ली-एनसीआर के बढ़ते प्रदूषण के मौलिक कारणों को समझना होगा, फिर उसका माकूल वैज्ञानिक हल निकालने का माकूल प्रयास करना होगा, अन्यथा इसका निदान बेहद मुश्किल प्रतीत होता रहेगा। आखिर बीते कई दशकों से 'सांप निकाल जाने के बाद लाठी पीने' की जो प्रशासनिक कवायद जारी है, उससे किसी का भी भला होने वाला नहीं है। खासकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों का तो कतई नहीं क्योंकि दिल्ली का न तो मौसम अपना है, न पानी। बस 'दलाली' की जिंदगानी से गुजर बसर चल रहा है।

यही वजह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई जिसमें प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों (जैसे BS3) के खिलाफ जांच और कड़ी कार्रवाई तेज करने तथा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। वाकई ये चिंताएं वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन को प्रमुख प्रदूषण स्रोत मानती हैं।

वहीं, सर्वोच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने 26 नवंबर 2025 को दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान गंभीर चिंता जताई और दो टुक शब्दों में कहा कि न्यायिक मंच के पास कोई रजदूरी की छड़ी नहीं है जो समस्या तुरंत हल कर दे। उन्होंने इसे स्वास्थ्य आपातकाल बताया और तत्काल निर्देश मागे ताकि लोगों को साफ हवा मिले। अपनी प्रमुख टिप्पणियां देते हुए सीजेआई ने कहा कि प्रदूषण के कारण

एकल नहीं बल्कि बहुआयामी हैं, इसलिए सभी कारणों की पहचान कर विशेषज्ञों से क्षेत्र-विशेष समाधान निकालने होंगे।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने प्रदूषण की नियमित निगरानी और सुनवाई पर जोर दिया, क्योंकि दिवाली के बाद मामले गायब हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने सरकार की समितियों की समीक्षा का आदेश दिया। साथ ही अगली सुनवाई के लिए 1 दिसंबर 2025 की तिथि मुकर्रर कर दी, जब व्यापक सुनवाई होगी। वहीं, व्यक्तिगत प्रभाव को स्पष्ट करते हुए सीजेआई ने स्वयं बताया कि प्रदूषण से सुबह की सैर बंद कर दी है क्योंकि टहलने के बाद सांस लेने में दिक्कत होती है और शाम को हवा अपेक्षाकृत बेहतर रहती है। कोर्ट वचुआल सुनवाई पर विचार कर रहा है। ये बयान समस्या की गंभीरता रेखांकित करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर वायु प्रदूषण के समाधान के लिए निम्न सिफारिशें मांगी हैं: पहला, प्रदूषण के सभी कारणों की व्यापक पहचान करने और विशेषज्ञों तथा वैज्ञानिकों को शामिल करते हुए क्षेत्र-विशेष समाधान निकालने की आवश्यकता पर जोर दिया है। दूसरा, सरकार द्वारा बनाई गई कमेटियों और उनसे मिली रिपोर्टों की समीक्षा करना ताकि उनके कामकाज और प्रभावकारिता को परखा जा सके। तीसरा, प्रदूषण की निरंतर मॉनिटरिंग और एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) की नियमित निगरानी को मजबूत करना। चतुर्थ, जलकाल और दीर्घकालिक उपायों पर ध्यान देना जिससे लोगों को तुरंत और स्थायी रूप से साफ हवा मिले। पांचवां, आगामी सुनवाई के नए उपायों की प्रगति और प्रभाव का आकलन करना। देखा जाए तो यह सिफारिशें प्रदूषण की जटिलता और उसकी बहुदूरी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए दी गई हैं, जिनका उद्देश्य तुरंत राहत देना और दीर्घकालिक सुधार सुनिश्चित करना है।

याद दिला दें कि नवतम मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदूषण रोकने के लिए एनर्जिसियों से पहले से तैयारी करने को कहा था, न कि स्थिति बिगड़ने पर प्रतिक्रिया देने को। तब कोर्ट ने निर्माण कार्यों पर



कौन बढ़ा रहा दिल्ली में प्रदूषण?

पूर्ण रोक खारिज कर दीर्घकालिक समाधान, जैसे हितधारकों की संयुक्त बैठकें, पर जोर दिया ताकि पर्यावरण और विकास का संतुलन बने। वहीं, चिंताओं की वैधानिक को स्पष्ट करते हुए कहा था कि कुछ चिंताएं अत्यधिक वैध हैं क्योंकि वाहन उत्सर्जन (दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण का प्रमुख कारण (लगभग 30-40%) है और पूर्व-कार्ययोजना की कमी से हर साल GRAP चरण लागू होते हैं। इसलिए कोर्ट का दीर्घकालिक फोकस व्यावहारिक है, क्योंकि अस्थायी उपाय जैसे पराली जलाना या निर्माण रोक असरदार साबित नहीं हुए, जबकि EV प्रोत्साहन और समन्वित प्रयास वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हैं।

समझिए, दिल्ली में प्रदूषण की मौलिक वजह क्या है?

उल्लेखनीय है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मौलिक वजह मुख्यतः औद्योगिक धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं, कचरा जलाना, निर्माण कार्य और सड़कों की धूल है। इसके अलावा, उत्तर भारत के निकटवर्ती जिलों से आने वाला प्रदूषण भी दिल्ली की हवा की गुणवत्ता को बेहद प्रभावित

करता है। पराली जलाना इस बार दिल्ली के प्रदूषण में अपेक्षाकृत कम योगदान देता है। मुख्य प्रदूषण स्रोत निम्नलिखित हैं-

पहला, औद्योगिक उत्सर्जन और अवैध कचरा जलाना दिल्ली में प्रदूषण का बड़ा कारण है। कई बार औद्योगिक और घरेलू कचरे की अवैध जलाने की घटनाएं घनी धुंध बनाने में सहायक होती हैं।

दूसरा, वाहनों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दिल्ली में भारी ट्रैफिक जाम और धीमी गति के कारण वाहन ईंधन अधिक जलाते हैं, जिससे जहरीली गैसों का उत्सर्जन बढ़ता है।

तीसरा, निर्माण स्थलों से निकलने वाली धूल और टूटी सड़कों की धूल भी वायु प्रदूषण में एक बड़ा योगदान देती है।

चतुर्थ, आस-पास के एनसीआर इलाकों से आने वाला प्रदूषण भी दिल्ली की हवा को जहरीला बनाता है।

पंचम, पराली और अन्य स्रोतों का योगदान सम्बन्धी हाल की रिपोर्टों के अनुसार, पराली जलाने का दिल्ली के कुल प्रदूषण में केवल लगभग

2% का योगदान है, जो पहले के वर्षों के मुकाबले कम माना गया है।

छठा, दिल्ली में खुले में कचरा जलाना, बायोमास जलाना, व गर्मी के मौसम में खाना पकाने से निकलने वाले धुएं का प्रदूषण में बड़ा हिस्सा होता है।

इस प्रकार, दिल्ली में प्रदूषण का समाधान औद्योगिकीकरण, वाहनों पर नियंत्रण, कचरा प्रबंधन, निर्माण कार्यों की निगरानी, और एनसीआर क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण के संयुक्त प्रयासों से ही संभव हो सकता है।

यही वजह है कि दिल्ली में वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देना, पुराने वाहनों पर सख्ती, रेट्रोफिटिंग डिवाइस लगाना और GRAP उपायों का कड़ाई से पालन मुख्य उपाय है, जो इस प्रकार हैं-

पहला, सरकारी नीतियां और पहल: EV नीति 2.0: अगस्त 2026 से नए पेट्रोल, डीजल और CNG दोपहिया वाहनों की रजिस्ट्रेशन पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा। CNG ऑटो रिक्शा को EV से बदलने का लक्ष्य है, साथ ही चार्जिंग स्टेशन बढ़ाए जाएंगे।

दूसरा, पुराने वाहनों पर कार्रवाई: BS-I और BS-III वाहनों (लगभग 37% कुल वाहन) के खिलाफ PMO ने रियल-टाइम ट्रैकिंग, AI-आधारित मॉनिटरिंग और सख्त जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं।

तीसरा, रेट्रोफिटिंग: DPCC द्वारा BS-III/IV वाहनों में कैटेलिटिक कन्वर्टर डिवाइस लगाने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू, जो PM10/PM2.5 को 70% तक कम कर सकता है। IIT दिल्ली और ICAT स्ट्रेटिंग करेंगे।

चतुर्थ, GRAP और अन्य उपाय: GRAP चरण-1/2 में सख्ती बढ़ाई गई है, जिसमें पुराने डीजल/पेट्रोल वाहनों पर पाबंदी, कंस्ट्रक्शन रोक और डीजल जनरेटर सीमित करना शामिल है।

पंचम, CNG का उपयोग बढ़ाएं, क्योंकि यह डीजल से बेहतर जलता है और प्रदूषण कम करता है।

छठा, कम सल्फर ईंधन, कैटेलिटिक कन्वर्टर और सख्त उत्सर्जन मानक (जैसे BS-VI) लागू करें।

सातवां, व्यक्तिगत कदमसर्वजनिक परिवहन या कारपूलिंग अपनाएं, पुराने वाहन स्क्रेप करें। EV खरीदने पर सब्सिडी लें और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करें।

यही वजह है कि दिल्ली में वाहनों से प्रदूषण कम करने वाली पॉलिसी में सबसे जल्दी प्रभाव पुराने वाहनों पर सख्त प्रतिबंध, GRAP के तत्काल उपाय और बॉर्डर पर BS-VI/CNG/EV-only एंट्री दिखाएंगे।

पहला, त्वरित वाहन वाली नीतियां: पुराने वाहनों पर तत्काल कार्रवाई: BS-III/BS-I वाहनों पर PMO के निर्देश से रियल-टाइम ट्रैकिंग, AI मॉनिटरिंग और जुर्माना लगाना। ये 37% वाहनों को लक्षित कर तुरंत उत्सर्जन घटाएगा।

दूसरा, GRAP चरण-1/2 सख्ती: पुराने डीजल वाहनों की पाबंदी, डीजल जनरेटर सीमित करना और कंस्ट्रक्शन रोक। हाल ही में GRAP-3 हटने पर भी ये उपाय जारी रहेंगे, जो AQI में तेज सुधार लाते हैं।

तीसरा, बॉर्डर एंट्री प्रतिबंध: नवंबर 2025 से केवल BS-VI, CNG या EV वाहनों को दिल्ली में प्रवेश, ANPR कैमरों से लागू। इससे बाहरी प्रदूषण स्रोत 30-40% कम हो सकते हैं।

चतुर्थ, अन्य तेज उपाय: रेट्रोफिटिंग डिवाइस: BS-III/IV वाहनों में कैटेलिटिक कन्वर्टर लगाना, जो PM को 70% तक घटाए। पायलट प्रोजेक्ट तुरंत शुरू हो चुका है।

पंचम, पीयूसीसी सेंटर ऑडिट और ट्रैफिक सिस्टम: द्विमासिक जांच से अनुपालन बढ़ेगा, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम जाम कम कर उत्सर्जन घटाएगा।

निःसन्देह, ये बदलाव 1-4 सप्ताह में AQI में 20-50 अंकों का सुधार दिखा सकते हैं, बशर्ते कड़ाई से लागू हो।

वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक

संविधान दिवस पर वरिष्ठ समाजसेवी मुसरफ खान का संदेश - संविधान तमी प्रभावशाली बनता है, जब नागरिक उसके अनुसार आचरण करें

तुम्हारी हर तकलीफ का मैं मुकम्मल जवाब हूँ, कभी वक्त मिले तो पढ़ना मैं भारत का संविधान हूँ।

आगरा, संजय सागर सिंह। संविधान दिवस के अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी मुसरफ खान ने कहा कि भारत यदि संविधान में निहित मूल्यों, सिद्धांतों और कर्तव्यों का अक्षर-पालन करे, तो वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य न सिर्फ संभव है, बल्कि सुनिश्चित भी है। भारत को 2047 तक विकसित देश बनाना हमारा साझा संकल्प है, और यह तभी साकार होगा जब हम संविधान को पूरी निष्ठा से अपनाएँ और उसे व्यवहार में उतारें।

मुसरफ खान ने कहा कि कोई भी संविधान चाहे जितना श्रेष्ठ क्यों न हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और राष्ट्रप्रेमी की सर्वोपरि रखने वाले न हों, तो उसके परिणाम भी सकारात्मक नहीं हो सकते। उन्होंने स्पष्ट किया कि संविधान तमी प्रभावशाली बनता है, जब नागरिक उसके अनुसार आचरण करें। संविधान दिवस हमें अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। भारतीय संविधान देश को संप्रभु, एकता और

लोकतांत्रिक गणराज्य की पहचान देता है और नागरिकों को व्यापक स्वतंत्रताएँ सुनिश्चित करता है।

संविधान एक जीवंत दस्तावेज़, भविष्य का मार्गदर्शक

वरिष्ठ समाजसेवी ने भारतीय संविधान की सार्वभौमिकता और उसकी जनकल्याणकारी भावना की सराहना करते हुए कहा कि संविधान मात्र कानूनी प्रावधानों का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन जीने का मार्गदर्शन है। यदि देश संविधान को पूरी ईमानदारी से लागू करे, तो भारत न्याय, समानता, विकास और मानवता का वैश्विक उदाहरण बन सकता है। बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि "भारत रत्न डॉ. अंबेडकर जी का संविधान दुनिया के श्रेष्ठतम लोकतांत्रिक दस्तावेज़ों में से एक है, जो हर नागरिक को समान अधिकार और सम्मान की गारंटी देता है।

महिला अधिकारों और राजनीतिक सशक्तिकरण पर बल

श्री खान ने आगे कहा कि डॉ. अंबेडकर जी ने सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करते हुए महिलाओं

के अधिकारों और सम्मान के लिए ऐतिहासिक पहल कीं, उनका यह महत्वपूर्ण योगदान भारत के सामाजिक और राजनीतिक एकीकरण में निर्णायक सिद्ध हुआ है। आज महिला नेतृत्व बढ़ने से लोकतांत्रिक मूल्य और अधिक सशक्त हो रहे हैं।

“भारत आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र”

उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता की दूरदृष्टि और समर्पण ने भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चुनावों में महिलाओं और युवाओं की बढ़ती भागीदारी देश के लोकतांत्रिक ढांचे को और मजबूत कर रही है। उन्होंने संविधान की तीनों शक्तियों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय संविधान सात दशकों से अधिक समय से हर चुनौती के बीच अपनी मजबूती और प्रासंगिकता साबित करता आया है।

संविधान की रक्षा हर नागरिक का दायित्व

वरिष्ठ समाजसेवी मुसरफ खान ने कहा कि संविधान हर नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान

करता है और किसी भी प्रकार के भेदभाव का विरोध करता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि संविधान केवल अधिकारों का दस्तावेज़ नहीं, बल्कि कर्तव्यों की भी प्रेरणा देता है। संविधान किसी भी मजहब या पंथ को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि राष्ट्र को सर्वोपरी मानता है। देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता बनाए रखने के लिए हर नागरिक को अपने कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है।

भावनात्मक शब्दों में उन्होंने कहा तुम्हारी हर तकलीफ का मैं मुकम्मल जवाब हूँ, कभी वक्त मिले तो पढ़ना... मैं भारत का संविधान हूँ।

अंत में राष्ट्रवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मुसरफ खान ने कहा कि यह दिवस डॉ. अंबेडकर जी के उस संघर्ष और संकल्प का प्रतीक है, जिसने भारत के वंचित और दबे-कुचले वर्गों को नए अधिकारों, सम्मान और अवसरों का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि संविधान कोई सामान्य दस्तावेज़ नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा है, जो हमें मंथुल, सामुदायिक सद्भाव, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रीय एकता का संदेश देता है। संविधान की रक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

द एमिनेंट रिसर्च, नई दिल्ली के द्वारा सम्मानित हुई "पंजाब रत्न" मनप्रीत कौर सेवा कार्यों के लिए मिला 'टॉप आइकन अवार्ड 2025' (डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)

वृन्दावन। ठाकुर बांके बिहारी महाराज की परमभक्त एवं संकट मोचन सेना (महिला प्रकोष्ठ), पंजाब की यशस्वी अध्यक्ष, प्रख्यात समाजसेवी रंजना रत्न श्रीमती मनप्रीत कौर (लुधियाना) इन दिनों समाजसेवा के क्षेत्र में अत्यधिक योगदान दे रही हैं। ब्रज वृन्दावन के प्रति उनका समर्पण व सेवाभाव अति प्रशंसनीय व सरहानीय है। इनके सेवाकार्यों की धूम समूचे देश में है। उन्होंने समूचे देश में विभिन्न सेवा प्रकल्प संचालित कर सते, निधनों व निराश्रितों की सेवा करने का संकल्प लिया हुआ है। इनके द्वारा रमां सीता रसोई व रमां राधा रसोई संचालित कर असंख्य लोगों को निःशुल्क भोजन व फलाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही वे देश के विभिन्न प्रांतों में अधिकाधिक अभावग्रस्तों की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने का कार्य कर रही हैं। उनके द्वारा किन्हीं निधन बच्चों को उनकी शिक्षा व वस्त्र आदि में, तो किन्हीं को उनकी चिकित्सा व मकान निर्माण आदि में आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है।

प्रख्यात समाजसेवी श्रीमती मनप्रीत कौर (लुधियाना) के इन्हीं सेवा कार्यों व समर्पण भाव को देखते हुए हारिका, नई दिल्ली के होटल रेडिसन ने द एमिनेंट रिसर्च, नई दिल्ली के द्वारा उन्हें सम्मानित करके 'टॉप आइकन अवार्ड 2025' प्रदान किया है। उन्होंने यह सम्मान प्रख्यात फिल्म अभिनेता चंकी पांडेय ने प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र आदि भेंट करके दिया।

ज्ञात हो कि 'पंजाब रत्न' श्रीमती मनप्रीत कौर (लुधियाना) को इससे पूर्व भी अनेक प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। ब्रज सेवा संस्थान, वृन्दावन के अध्यक्ष एवं प्रख्यात साहित्यकार 'यूपी रत्न' डॉ. गोपाल चतुर्वेदी ने श्रीमती मनप्रीत कौर को 'टॉप आइकन अवार्ड 2025' मिलाने पर हर्ष व्यक्त किया है।

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा एवं तेलंगाना एंटी-नारकोटिक्स ब्यूरो का संयुक्त अभियान

स्वतंत्र सिंह भुल्लर नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और तेलंगाना एंटी-नारकोटिक्स ब्यूरो (IGNAB), हैदराबाद ने संयुक्त रूप से एक व्यापक और रणनीतिक अभियान चलाकर दिल्ली-NCR में सक्रिय एक बड़े ड्रग्स ट्रेडिंग एंटीकी इन कार्टेल का सफ़ातापूर्वक भंडाफोड़ किया है। यह कार्रवाई दोनो राज्यों के बीच अब तक के सबसे प्रभावी और बड़े समन्वित अभियानों में से एक के रूप में उभरकर सामने आई है, जिसमें कई दिनों के तकनीकी व मानवीय इन्फ्यू, निगरानी, गहन विश्लेषण और सावधानीपूर्वक योजना के साथ दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों—फैक्ट्री, संगठन, नीतीति, प्रताप एन्कलेव, मुनीकरा और केटर नोटिस—में एक साथ सर्च ऑपरेशन की गई। इस पूरे अभियान की सुरक्षा तह हूड तेलंगाना एंटी-नारकोटिक्स ब्यूरो ने अपने दर्ज नुम्बरों FIR No. 08/25 के संदर्भ में WR-1, क्राइम ब्रांच को सूचना दी कि प्रमुख आरोपी और उनके सहयोगी दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर छिपे हुए हैं। सूचना को पृष्ठ लेने के बाद दिल्ली पुलिस और IGNAB ने कई दिनों तक मेहनत करते हुए टिकानों की पहिचान किया और फिर एक well-coordinated प्लान के तहत टीमों के साथ की गई। इस अभियान का नेतृत्व तेलंगाना पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया जबकि दिल्ली पुलिस की ओर से ACP/WR-1 श्री सहदेव गौतम के पर्यवेक्षण और DCP/Crime Branch श्री रविंद्रो, IPS की समन्वय देखरेख में कार्रवाई को तंत्रित किया गया। ऑपरेशन टीम में इन्स्पेक्टर अमित मलिक, इन्स्पेक्टर अरिंजित वाजपेयी, इन्स्पेक्टर मीराल सिंघ, इन्स्पेक्टर अरुण गल्लोत, इन्स्पेक्टर अरविंद, SI अमित, SI अरिंजित, SI नौरव, SI प्रदीप, W/SI गौतम, ASI सखवीर, W/ASI निरंकर कौर सहित कई अनुभवी अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने कई स्थानों पर एकसाथ छापेमारी कर इस अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की जड़ को बड़ी गहराई से उखाड़ फेंका।

डे के दौरान सबसे प्रमुख बरामदगी मोल्ड गार्डन, ब्रज नगर से हुई जहां 35 वर्षीय युवाओं की महिला गैंगबन्धुओं की टीम का निगरान किया गया। इसकी तलाशी में 195 ग्राम कोकीन, 24 ग्राम MDMA और 40,500 नकद बरामद हुए। इस अपराध पर FIR No. 344/25 U/s 11/25/25 NDPS Act दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। इसी तरह तिलक नगर के संगठन इलाके में 49 वर्षीय नाइजीरियाई महिला बेकी @ बेकी को पकड़ा गया जिसके कब्जे से 5,209 Ecstasy (MD) गोलीबंदी, 35.46 ग्राम कोकीन और 78,000 नकद बरामद हुए।



यह बरामदगी दर्शाती है कि वह बड़े स्तर पर नशीले पदार्थों के वितरण में शामिल थी। जब पूछताछ में उसने बताया कि उसने हाल ही में "Frank" नाम के नाइजीरियाई नागरिक को सामान सौंपा दिया है, तो टीम ने तुरंत बंदर विहार, निराल विहार में छापे मारा और उसके कब्जे से 60 MD Pills जरा कर उसे गिरफ्तार किया गया। Frank पूर्व में भी NDPS और Foreigner Act के केस FIR No. 376/23 में जेल जा चुका है, और इस बार भी उसके पास से 40.33 ग्राम कोकीन बरामद हुई। दूसरी महत्वपूर्ण कार्यवाही locked premises पर की गई जहाँ तेलंगाना में वॉरिंट आरोपी जौन अरुण्ड @ गॉडविन के किराये के मकान की तलाशी में 106.38 ग्राम कोकीन और 107.83 ग्राम स्टेडन बरामद हुईं। यह स्थान कार्टेल के लिए एक सुरक्षित 'स्टॉक व्हाइंड' के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। इस बरामदगी पर FIR No. 345/2025 U/s 11/25 NDPS Act दर्ज कर कार्रवाई की गई। ये सभी बरामदगियाँ इस बात का प्रमाण गूढ़, एस. जोगुआ गूढ़ और ताल खोईसैं सैलियन शामिल हैं। ये सभी तेलंगाना पुलिस की FIR No. 08/25 में वॉरिंट थे और इन गैंगों की हेरफेर, अद्वैत फंडिंग, SIM कार्ड सत्यापन, गुनगान कम्प्यूटेशन के तहत तैयार करने और लॉजिस्टिक सहायता देकर कार्टेल को मजबूत करते हैं। बरामदगी और कार्टेल के मुख्य फाइनेंशियल मैनेजर के रूप में काम करते थे, जो इसकी कार्रवाई को सुरक्षित बनाने से आगे बढ़ते थे। वहीं साम्राज्य, जो बरामदगी की पत्नी है, लॉजिस्टिक और आर्थिक समर्थन में सहायता देकर पूरे नेटवर्क की बेकवर्ड ऑपरेशंस को

चलाती थी। दूसरी ओर दिल्ली गूढ़, एस. जोगुआ गूढ़ और ताल खोईसैं सैलियन SIM कार्ड सत्यापन के प्रमुख ऑपरैटर थे, जो विदेशी नागरिकों को प्रॉक्सि और फ़ॉर्ज पद्यान पर डेम उपलब्ध कराते थे ताकि वे लगातार मोबाइल नंबर बदलकर पुलिस की निगरानी से बच सकें। यह पूरा निरोध विदेशी घेस्टर्स के लिए एक नज़रूत 'सॉल्ट मिस्ट्रन' तैयार करता था, जिसकी वजह से कार्टेल लंबे समय से सक्रिय रह सका। सभी गिरफ्तार आरोपियों को आगे की कानूनी कार्रवाई हेतु IGNAB को सौंप दिया गया है।

पूरी कार्रवाई के दौरान पुलिस को 30 विदेशी नागरिक (12 महिलाएं और 18 पुरुष) अद्वैत रूप से दिल्ली में रखे हुए बिने। ये सभी अलग-अलग किराए के मकानों में बिना वेध दरतावेजों के रह रहे थे और इन नेटवर्क की जमीन स्तर पर सक्रिय रखने का काम कर रहे थे। इनमें से 18 पुरुषों को Deportation Facility नैज दिया गया है जबकि 12 महिलाओं के प्रस्ताव फ़रओ के साथ समन्वय में कानूनी प्रक्रिया चल रही है। इस कार्रवाई ने स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली-NCR अद्वैत विदेशी नागरिकों के लिए इन नेटवर्क के तहत एक सुरक्षित ठिकाना बन रहा था, जिसे तोड़ने के लिए यह संयुक्त अभियान अत्यंत आवश्यक था। यह संयुक्त अभियान अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स टस्करी के एक बड़े नेटवर्क को जड़ से तोड़ने में मौत का पत्थर साबित हुआ है। यह नेटवर्क कोकीन, MDMA, स्टेडन और हेरॉइन जैसे उच्च-मूल्य नशीले पदार्थों की टस्करी में शामिल था और अपने संचालन के लिए अद्वैत रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को किराये के रूप में प्रयोग करता था। यह कार्टेल किराए के घरों में छिपकर काम करता था, वहीं भारतीय फ़ैसिलिटेटरों के जरिए SIM कार्ड सत्यापन, सुरक्षित कम्प्यूटेशन, इन गैंगों की आवाजारी और नेटवर्क के विस्तार में सहायता मिलती रही है। इस संयुक्त कार्रवाई ने एक ही बार में इस नेटवर्क के सत्यापन, फंडिंग वैनल और कम्प्यूटेशन सिस्टम तीनों को घोट-घुड़वाई है। दिल्ली पुलिस और तेलंगाना पुलिस ने पुनः स्पष्ट किया है कि इन टस्करी और अद्वैत विदेशी नागरिकों पर कार्रवाई उनकी प्राथमिकताओं में शीर्ष पर रहेगी। जांच एजेंसियाँ अब नेटवर्क के बचे हुए सदस्यों, उनके अंतरराष्ट्रीय संपर्कों, फंडिंग स्रोतों और विदेशी लिंक की पहिचान के लिए आगे की जांच जारी रखेंगी, ताकि इस पूरे कार्टेल को पूर्ण रूप से उखाड़ फेंका जा सके।

यूपी में बड़ा फैसला! अब आधार कार्ड से नहीं चलेगा काम!

पिकी कुंडू
सदस्य बंगाली प्रकोष्ठ भाजपा दिल्ली प्रदेश
सदस्य उज्ज्वला योजना भाजपा दिल्ली प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार ने आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र या अधिकृत जन्म तिथि के सबूत के रूप में मान्य करने पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश प्लानिंग विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने सभी विभागों को आदेश जारी कर स्पष्ट निर्देश दिए हैं की

1. आधार कार्ड के साथ कोई जन्म प्रमाण पत्र अटैच नहीं होता
2. इसलिए आधार को जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर स्वीकार ना किया जाए

अब सरकारी कामों में जन्म तिथि के लिए केवल मान्य जन्म प्रमाणपत्र ही मान्य होगा, आधार कार्ड की डीओबी प्रूफ के तौर पर नहीं माना जाएगा, इस आदेश के जारी होने से यूपी में लाखों लोगों पर पड़ेगा इसका असर और आवेदन वैरिफिकेशन प्रोसेस में होगा बड़ा बदलाव !



वैदिक काल से ही होता रहा नारियों का सम्मान: मंजू पारीक (डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)

वृन्दावन। नगर निगम बालिका इंटर कॉलेज में इनर व्हील क्लब ऑफ वृन्दावन, दिव्य शक्ति के तत्वावधान में भारत सरकार के नारी सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत सशक्त नारी सशक्त भारत कार्यक्रम क्लब की अध्यक्ष निशा शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। जिसमें मथुरा जनपद के चार प्रमुख विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं का सम्मान एवं अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डिसेंबर 311 की आइ.एस.ओ. मंजू पारीक ने कहा कि वैदिक काल से ही नारियों का सम्मान भारत की परंपरा रहा है। भारत की नारियों में आपला, सीता, गार्गी, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अहिल्याबाई, द्रौपदी आदि ऐसी महिलाएं हुई हैं, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व से समाज को एक नई दिशा दी है। आज भी देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं ने अपनी योग्यता के बल पर देश को अपनी सेवा के माध्यम से दिशा दी है। अध्यक्ष निशा शर्मा ने बताया कि सम्मान समारोह में चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर वार्तिका किशोर, न्याय के क्षेत्र में प्रतिभा शर्मा, शिक्षा के क्षेत्र में पूनम चौबे और पुलिस विभाग में कार्यरत इस्मिंत पंवार को इमंडलीय आदर्श नारी दुर्गा शक्तिर सम्मान से अलंकृत किया गया। साथ ही उन्हें प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और पटका-प्रसाद आदि भेंट किया गया। सम्मानित हुई प्रमुख शिक्षाविद् पूनम चौबे ने कहा के शिक्षा के बल पर राष्ट्र को उन्नतशील बनाया जा सकता है। अधिवक्ता प्रतिभा शर्मा ने बताया कि बालिकाओं पर होने वाले अपराधों व परेशानियों को किस प्रकार से कानूनी सहायता मिल सकती है। पुलिस विभाग में कार्यरत सिता पंवार ने महिला पुलिस के कर्तव्य के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर वार्तिका किशोर ने सर्वांगकल कैंसर चिकित्सा के बारे में सैकड़ों बालिकाओं का ज्ञानवर्धन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में संयोजिका नीरा शर्मा, पूर्व अध्यक्ष संध्या शर्मा, कोषाध्यक्ष शशि शर्मा, ममता श्रीवास्तव, सारिका, मनीषा, पुष्यलता, रेनु, छाया, श्री शॉडिल्य, शशि का आचार्य व संध्या शर्मा आदि की उपस्थिति विशेष रही।

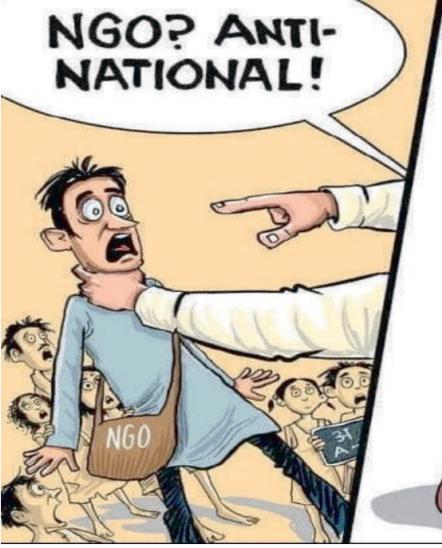


आरएसएस की अमरीका में लॉबिंग

(आलेख : राम पुनिया, अनुवाद : अमरीश हरदेनिया)

आरएसएस के शताब्दी वर्ष में इस संगठन के बारे में एक ऐसा तथ्य सामने आया है, जिसकी जानकारी बहुत लोगों को नहीं थी। कई यूट्यूब चैनलों पर चर्चा है कि आरएसएस ने अमरीका में एक लॉबिंग फर्म की सेवाएं लेना शुरू की हैं। दिलचस्प बात यह है कि यही फर्म पाकिस्तान के लिए भी लॉबिंग कर रही है। स्मरणीय है कि नरेन्द्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने भी अपनी छवि उजली बनाने के लिए एक फर्म की सेवाएं ली थीं... रवाशिगटन स्थित फर्म एपीसीओ वर्ल्डवाइड को अगस्त 2007 में अहम-विधानसभा चुनाव के ठीक पहले दुनिया के सामने मोदी की छवि बेहतर बनाने के लिए नियुक्त किया गया था। 'संयोग की बात है कि एपीसीओ, जो एक अमरीकी कानूनी फर्म की सहायक फर्म है, ने कई तानाशाहों की छवि सुधारने का काम भी किया था। 'यहां तक कि इस फर्म की सेवाएं लेने वाले देशों के लिए जब-जब जंग फायदे का सौदा नजर आई, तब उसने जंग के पक्ष में भी अभियान छेड़े थे। ऐसा लगता है कि लॉबिंग छवि को उजला बनाने के अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। लॉबिंग से रसही सामूहिक समझ निर्मित होती है और रसहमति का उत्पादन करने में मदद मिलती है। 'सहमति के उत्पादन' का सिद्धांत प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता नोएम चोमोस्की ने प्रतिपादित किया था। 'द प्रिंट' और कई अन्य स्रोतों ने खबर दी है कि समाचार सेवा रॉयटर्स द्वारा की गई पड़ताल के मुताबिक इस फर्म को अमरीकी सीनेट, हाऊस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और अमरीकी अधिकारियों के बीच आरएसएस की लॉबिंग करने के लिए 3.30 लाख डॉलर दिए गए हैं। इस अमरीकी समाचार सेवा ने जो जानकारीयें जुटाई हैं, उनके मुताबिक 2025 की तीन शुरुआती तिमाहियों के दौरान इस रकम के एक बड़े हिस्से का भुगतान किया गया। प्रिंट द्वारा देखे गए कई सार्वजनिक दस्तावेजों से पता लगता है कि आरएसएस ने 3 मार्च से इस फर्म के सेवाएं लेना शुरू किया।

इस धनराशि का स्रोत क्या है? आरएसएस एक अर्जेंटिकृत संस्था है और उसका दावा है कि उसकी आय का एकमात्र स्रोत 'गुरु दक्षिणा' है। एक अर्जेंटिकृत संस्था द्वारा अमरीकी कानूनी रकम खर्च करना आम घटना नहीं है। आरएसएस के श्री अंबेकर ने इस खबर का खंडन किया है, मगर यह जानकारी कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइटों और अमरीकी सीनेट की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। वह इसलिए, क्योंकि अमरीका में कंपनियों के



लिए विदेशी स्रोतों से प्राप्त राशि की घोषणा करना अनिवार्य है।

इसके पहले इस अर्जेंटिकृत संस्था की जांच आयकर से जुड़े मामलों में की गई थी। इसके प्रकरण की जांच करने वाले न्यायाधिकरण ने कहा था, 'गुरु दक्षिणा की परंपरा कुतजता के जिस पवित्र भाव पर आधारित है, उसे महसूस करते हुए न्यायाधिकरणों ने आरएसएस द्वारा इस तरह एकत्रित की गई धनराशि पर कर में छूट दी थी। किंतु गुरु दक्षिणा का मूल चरित्र उस समय पूरी तरह से बदल जाता है, जब 'गुरु' इस निधि का इस्तेमाल एक विदेशी संस्था को एक विदेशी सरकारी से अपनी लॉबिंग करने के लिए करता है... तब भी जब हम 'लॉबिंग' की व्याख्या विदेशी सरकारी अधिकारियों को 'शिक्षित' करने के रूप में करें'।

आखिर लोगों को बांटने वाली यह संस्था - जो कुछ साल पहले तक सालेंट मोड में काम करने में भरोसा रखती थी - को अमरीकी कंपनी की सेवाएं लेने और किसी मध्यस्थ के जरिए उसे अमरीकी नीति-निर्धारकों और वहां की जनता के समक्ष अपनी छवि बनाने के लिए धनराशि का भुगतान करने की जरूरत क्यों पड़ी? तथ्य यह है कि आरएसएस-भारतीय जनसंघ-भाजपा की नीतियां मोटे तौर पर सदैव और विशेषकर 1950 और 1960 के दशकों में अमरीकी नीतियों के अनुरूप रही हैं। इन्होंने अमरीका के वियतनाम पर हमले का समर्थन किया,

दुनिया के विभिन्न स्थानों पर अमरीकी आक्रमणों को सही बताया और उस दौर में भारत सरकार पर अमरीका-समर्थक नीतियों अपनाते का दबाव डाला, जब भारत गुटनिरपेक्षता और सोवियत रूस, जिसे पश्चिम अपना पक्का दुश्मन मानता था, समेत कई देशों की मदद से आधुनिक संस्थानों की स्थापना कर लाभान्वित हो रहा था।

कई भारतीय, जो देशभक्त होने का दावा करते हैं, लेकिन डालर के लालच में अमरीका में बसे हुए हैं, अपने मूल देश के संस्कारों को बचाए रखने और अपनी नई पीढ़ी में ये संस्कार डालने हेतु इस दक्षिणपंथी संस्था के समर्थक हैं और थे। इनमें से कई घोर आरएसएस-भाजपा समर्थक अमरीका में उच्च राजनैतिक पदों पर आसीन हैं। ऐसे में इस तरह की लॉबिंग की जरूरत ही क्या है?

बात यह है कि कुछ नए हालात पैदा हुए हैं, जिनके चलते यह संस्था ऐसा करने को बाध्य हुई है। पहला यह है कि आरएसएस स्वयं को अमरीका-समर्थक के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। यह इस तथ्य के बावजूद कि हाल में भारत कई मामलों में अमरीकी विदेश नीति का अनुसरण नहीं कर रहा है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि कई अमरीकी संस्थाएं, जो सरकार का हिस्सा नहीं हैं या सारे विश्व में मानवाधिकारों की स्थिति की निगरानी करती हैं, भारत में मानवाधिकारों के हनन पर रोशनी डाल रही हैं और आरएसएस के असमानता-

समर्थक रवैये की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करा रही हैं। आरएसएस, हिन्दू स्वयंसेवक संघ (एचएसएस) के नाम से अमरीका में सक्रिय है। भारतीय मूल के हिन्दुओं की एक अन्य संस्था है 'हिन्दू फॉर ह्यूमन राइट्स' जो उदार मूल्यों की पक्षधर है।

अमरीका में कार्यरत कई अन्य संगठन भी संघ परिवार की कारगुजारियों पर विस्तृत रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। 'द इंडियन रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट-2024' में भारत में घटती हुई धार्मिक स्वतंत्रता का विवरण दिया गया है : रस-2023 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता में कमी आने का क्रम जारी रहा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने भेदभावपूर्ण राष्ट्रवादी नीतियों को मजबूती दी, नफरती बातों को हवा दी और सांप्रदायिक हिंसा पर रोक नहीं लगाई। इस सांप्रदायिक हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित मुसलमान, ईसाई, सिक्ख, दलित, यहूदी और आदिवासी हुए। गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम (यूपीए), विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम (एफसीआर), निगरानिका संशोधन अधिनियम (सीएए) व धर्मान्तरण और गौधव से संबंधित कानूनों का इस्तेमाल मनमाने ढंग से लोगों को हिरासत में लेने के लिए किया गया। धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनके हकों की बात करने वालों को निशाना बनाया गया। (यूएस कमिशन ऑन इंटरनेशनल

रिलीजियस फ्रीडम - यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट से)।

प्रतिष्ठित रास संटर फॉर सिक्क्यूरिटी ऑफ़ रेस एंड राइट्स ने डेनवर व कोलंबिया विश्वविद्यालयों के अध्येताओं के सहयोग से नफरत, सांप्रदायिक राष्ट्रवाद और हिंसा फैलाने में संघ परिवार की भूमिका पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। यह संस्था 9/11 (2001) के हमले के बाद से ही मुस्लिम, अरब और दक्षिण एशियाई समुदायों के हालात पर नजर रख रही है। ये समुदाय उस हमले के बाद से ही भेदभाव और पूर्वाग्रहों के शिकार रहे हैं। विविधताओं से भरे इन समुदायों के बारे में जानकारी के अभाव के चलते, उनकी गलत छवि प्रस्तुत की जा रही है, उन्हें एकसार बताया जा रहा है और उन्हें और इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है। 'द सेंटर फॉर सिक्क्यूरिटी, रेस एंड राइट्स' धर्म और नस्ल से परे, अरब, अफ्रीकी और दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के प्रति नफरत और डर के भाव और इस्लामोफोबिया के मूल में जो संरचनात्मक और प्रणालीगत कारण हैं, उनसे निपटने के लिए काम कर रही है। इसकी रिपोर्ट में अमरीका में हिंदुत्व की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है, विशेषकर इस दृष्टि से कि हिंदुत्ववादी गतिविधियां किस तरह समानता और बहुलतावाद के लिए नस्लीय-राष्ट्रवादी खतरा हैं। यह बताती है कि किस तरह मुसलमानों और अरबों का दानवीकरण हो रहा है

और उनके बारे में किस तरह की नफरती बातें कही जा रही हैं।

अमरीका में भी हिंदुत्व चिंता का विषय है। इस रिपोर्ट में हिन्दुत्ववादियों की उनके एजेंडा से जुड़ी गतिविधियों को उजागर किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह हिन्दू राष्ट्रवादी समूह अमरीका में हिन्दू धर्म के संकीर्ण और राजनीति पर आधारित संस्करण को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा, हिन्दुत्ववादी, ऊंची जातियों के वर्चस्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पैरोकार हैं और अन्य धर्मों के प्रति असहिष्णुता का भाव रखते हैं। यह महत्वपूर्ण रिपोर्ट, एचएसएस और व्हीएचपीए जैसी संस्थाओं की भूमिका पर प्रकाश डालती है, जो बाल विहार और बाल गोकुलम जैसे समर्थक हैं और युवाओं के लिए कार्यक्रमों का इस्तेमाल बच्चों के मन में हिंदुत्व के मूल्य बिठाने के लिए करते हैं। वे उनके मन में गैर-हिन्दुओं के प्रति पूर्वाग्रह पैदा कर रहे हैं और जातिगत ऊंच-नीच को मजबूती दे रहे हैं।

इस तरह की रिपोर्टों और अमरीका में हिंदुत्व के बढ़ते विरोध के चलते ही शायद आरएसएस को अपनी छवि सुधारने के लिए लॉबिंग फर्म की सेवाएं लेने की जरूरत पड़ी है। (लेखक आईआईटी मुंबई में पढ़ाते थे और सेंटर फॉर स्टडी ऑफ़ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म के अध्यक्ष हैं।)

बहुपत्नीत्व अब इतिहास असम ने बदल दी सदियों की परंपरा

27 नवंबर 2025 का दिन असम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। इसी दिन विधानसभा ने भारी बहुमत से "असम प्रोहिबिशन ऑफ़ पॉलीगैमी बिल-2025" पारित कर वह कदम उठाया, जिसकी गूंज आने वाले दशकों तक सुनाई देगी। इस कानून के तहत अब कोई भी व्यक्ति जीवित पत्नी के रहते दूसरी शादी करेगा तो उसे सात वर्ष का कारावास भुगतान होगा, और यदि यह शादी छिपाकर की गई है तो सजा बढ़कर दस वर्ष तक पहुंच जाएगी, साथ ही अलग से भारी जुर्माना भी देना होगा। दंड केवल जेल और जुर्माने तक सीमित नहीं है—दोषी को जीवनभर किसी भी सरकारी नौकरी, चाहे वह चपरासी स्तर की हो या आईएसएस जैसी उच्च सेवा से वंचित कर दिया जाएगा।

साथ ही, पंचायत से लेकर नगर निगम तक किसी भी पद का चुनाव नहीं लड़ सकेगा और राज्य की सभी कल्याणकारी योजनाएँ, पेंशन तथा राशन सुविधाएँ भी तुरंत बंद हो जाएंगी। इतना ही नहीं, यदि कोई काजी, मौलवी, पंडित या सरपंच ऐसी गैर-कानूनी शादी संपन्न कराता है, तो उसे दो साल की सजा और डेढ़ लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि माता-पिता या रिश्तेदार यदि विवाह से जुड़े तथ्य छिपाते पाए जाते हैं, तो उन पर भी एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यह कानून हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख—सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होगा; हाँ, छठी अनुसूची के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपनी स्थानीय परिषदों के माध्यम से इसी प्रकार का समान कानून लागू करने का निर्णय स्वयं ले सकेंगी हैं।

मुख्यमंत्री हिमाचल बिस्वा सरमा ने विधानसभा में कहा, "यह बिल किसी धर्म के विरुद्ध नहीं, बल्कि उन कुरीतियों को खिलाने में जिन्होंने सदियों से औतक बंधन रखा है। तुर्की, ट्यूनीशिया जैसे कई मुस्लिम देशों में पॉलीगैमी पहले से प्रतिबंधित है, और पाकिस्तान में भी दूसरी शादी

के लिए पहली पत्नी की लिखित अनुमति जरूरी है। असम ने केवल न्याय और सच्चे धर्म का साथ दिया है।" उन्होंने साफ कहा कि यही यूनिफॉर्म सिविल कोड की पहली सौढ़ी है, और 2026 में सरकार दोबारा बनी तो पूरा यूसीसी लागू किया जाएगा।

सच यह है कि बहुपत्नीत्व कभी किसी का "धार्मिक अधिकार" नहीं था, यह हमेशा पुरुष की सुविधा और स्त्री की मजबूती का हथियार रहा। पहली पत्नी को भावनाओं सहित कैद कर देना, उसके कोठे को आर्थिक-मानसिक रूप से तोड़कर दूसरी-तीसरी शादी रचाना—क्या यही मर्दानगी है? एनएफएचएस-5 बताता है कि पूर्वोत्तर के हजारों परिवार आज भी इसी जबर से धीमे-धीमे टूट रहे हैं। पहली पत्नी के पास न तलाक का अधिकार बचता, न गुजारा भत्ता, न वारिस में बराबरी; बच्चे नई शालिवादी की दहलीज पर ही पिस जाते हैं। असम ने निर्णायक निर्णय लिया—अब बस। अब औरत का हक, किसी भी धर्म की आड़ से ऊपर रखा जाएगा।

यह कानून केवल सजा का हथियार नहीं, समाज को नई नींव देने वाला क्रांतिकारी दस्तावेज है। पीड़ित महिला को तुरंत मुआवजा, मुफ्त कानूनी सहायता और सरकारी सुरक्षा कवच मिलेगा। पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार होगा, जबकि दोबारा अपराध करने वाले को दोगुनी—यानी बीस वर्ष तक—की कठोर सजा भुगतनी पड़ेगी। ये प्रावधान इतने सख्त और स्पष्ट हैं कि अब कोई पुरुष दूसरी शादी का ख्याल भी मन में लाए तो उसका खून जम जाए। बहुपत्नीत्व की सदियों पुरानी जंजीर अब हमेशा के लिए टूट चुकी है—असम ने सिर्फ कानून नहीं बनाया, उसने आने वाली नरकों के लिए एकपत्नीत्व को अनिवार्य जीवन-मूल्य बना दिया।

अब बारी बाकी राज्यों की है। उत्तराखंड ने यूसीसी लागू किया, और असम उससे भी कठोर कानून लेकर आगे निकल गया। गुजरात, हिमाचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान

और उत्तर प्रदेश—सबकी सरकारें अब जनता के तीखे सवाल का सामना करेंगी। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और तेलंगाना जैसे राज्यों में, जहां एनएफएचएस डेटा आज भी 2-3% पॉलीगैमी दिखाता है, उन्हें जवाब देना होगा—आखिर आप कब जागेंगे? असम ने साबित कर दिया कि धार्मिक वोटबैंक के डर से मुक्त होकर भी महिलाओं के अधिकारों की निर्णायक लड़ाई लड़ी जा सकती है। यह हिंदू कोड बिल-1955 के बाद की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति है।

इस कानून से समाज की तस्वीर बदल जाएगी। पहली पत्नी को उसका हक और सम्मान मिलेगा, और बच्चे एक स्थिर परिवार में बड़े होंगे। लड़कियों को पढ़ाई-लिखाई पर ध्यान जाएगा, क्योंकि मां-बाप अब यह डर नहीं रखेंगे कि उनकी बेटी किसी की 'दूसरी' बन जाएगी। संपति विवाद घटेंगे, और सबसे बड़ी बात—समाज में औरत अब केवल "घर वाली" नहीं, बल्कि बराबर की हिस्सेदार मानी जाएगी। विरोध करने वालों के लिए बस दो सवाल हैं—पहला, अगर हिंदू या ईसाई एक से ज्यादा शादी करता है तो आप सजा को बात करते हैं, लेकिन मुस्लिम करे तो 'धार्मिक अतिक्रम' ? यह दोहरा मापदंड क्यों? दूसरा, क्या औरत का सम्मान और उसकी सुरक्षा धर्म से बड़ी चीज नहीं?

असम ने इन सवालों का जवाब कानून बनाकर दे दिया है। अब इतिहास खुद गवाह बनेगा कि 2025 में एक छोटे से राज्य ने पूरे देश को नारी-न्याय का पाठ पढ़ाया। हिमंता बिस्वा सरमा की सरकार ने यह साबित कर दिया कि अगर साहस हो तो असंभव कुछ भी नहीं। "एक पुरुष, एक पत्नी"—यह केवल कानून नहीं, बल्कि नई सदी का सामाजिक धर्म है। असम ने राह दिखाई, मानक तय किए, और अब पूरे भारत को उस राह पर चलना है। यह केवल एक निर्णय नहीं, बल्कि समाज के लिए जागृति और महिलाओं के अधिकारों की असली विजय है।

प्रो. आरके जैन "अरिजित",

विकसित भारत: सुरक्षा आयाम- 60वां अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक सम्मेलन 29-30 नवंबर 2025

भारत वैश्विक शक्ति बनने की अपनी आकांक्षा को सुरक्षा दृष्टि से भी पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में सक्षम 60वें सम्मेलन में वामपंथी उग्रवाद आतंकवाद-निरोध, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा साइबर अपराध और फोरेसिक विज्ञान एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर चर्चा मिल का इत्थर साबित होगी- एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तर पर भारत की आंतरिक सुरक्षा संरचना को अधिक मजबूत, अधिक तकनीक-आधारित और अधिक भविष्य-संवेदी बनाने की दिशा में 60वां अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक सम्मेलन एक ऐतिहासिक पड़ाव के रूप में उभर कर सामने आया है। यह सम्मेलन 28 से 30 नवंबर 2025 तक नया रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान में आयोजित हो रहा है। इसमें देश के गृह मंत्री पहले ही शामिल हो चुके हैं, जबकि प्रधानमंत्री और निरंतर परिवर्तनशील देश में सुरक्षा प्रशासन अब केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित मुद्दा नहीं रहा है जहां राष्ट्रीय सुरक्षा से भी अधिक राष्ट्रीय दृष्टिकोण का अभिन्न और केंद्रीय घटक बन चुका है। विकसित भारत: सुरक्षा आयाम विषय-सार इस सम्मेलन की यही भावी और भू-आयामी दिशा दर्शाता है। इसमें वामपंथी उग्रवाद आतंकवाद-निरोध, आपदाप्रबंधन महिला सुरक्षा, साइबर-अपराध और फोरेसिक विज्ञान एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग जैसे विषयों पर गहन विचार-विमर्श हो रहा है। इन सभी क्षेत्रों में पिछले वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, और अब आवश्यकता है कि इन उपलब्धियों को एकीकृत कर एक ऐसे सुरक्षित भारत का निर्माण किया जाए, जो वैश्विक शक्ति बनने की अपनी आकांक्षा को सुरक्षा दृष्टि से भी पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके। यह सम्मेलन मूलतः एक ऐसे संवादात्मक मंच के रूप में विकसित हुआ है जहां राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े उच्चतम स्तर के निर्णयकर्ता पुलिस प्रशासन की वास्तविक चुनौतियों पर खुलकर चर्चा करते हैं। भारत जैसे विशाल, विविधतापूर्ण और निरंतर परिवर्तनशील देश में सुरक्षा चुनौतियाँ स्थिर नहीं हैं; वे लगातार रूप बदलती हैं, क्षेत्र विशेष के हिसाब से अपना अलग रूप लेती हैं और समय-समय पर तकनीकी, सामाजिक और भू-राजनीतिक स्वरूपों में विकसित हो रही रहती हैं। ऐसे वातावरण में पुलिस बलों के बीच अनुभवों का साझा होना, विभिन्न राज्यों के मॉडल का तुलनात्मक

अध्ययन, और केंद्र तथा राज्य सरकारों के स्तर पर एक एकीकृत राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टिकोण तैयार करना अत्यंत आवश्यक है। यह सम्मेलन वर्षों से इसी भूमिका को निभाता आया है, मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूँ कि 2025 का यह संस्करण अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत अब 2030 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में पहुँचने का लक्ष्य ले चुका है, और विकसित राष्ट्र बनने का अर्थ आर्थिक उन्नति भर नहीं, बल्कि उच्च स्तरीय फेरुल सुरक्षा संरचना भी है।

साथियों बात अगर हम इस वर्ष के सम्मेलन की कड़ों से यह वामपंथी उग्रवाद पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रहा है। पिछले एक दशक में वामपंथी हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है, लेकिन पूरी तरह से इसका उन्मूलन अभी शेष के रूप में उभर कर सामने आया है। यह वामपंथी उग्रवाद केवल पुलिस युद्ध नहीं है, यह सामाजिक विश्वास बहाली विकास की पहुंच, स्थानीय शासन के सुदृढ़ीकरण और सामुदायिक भागीदारी से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। 30 नवंबर को अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इतने उच्च-स्तरीय नेतृत्व की प्रत्यक्ष भागीदारी यह दर्शाती है कि भारत में सुरक्षा प्रशासन अब केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित मुद्दा नहीं रहा है जहां राष्ट्रीय सुरक्षा से भी अधिक राष्ट्रीय दृष्टिकोण का अभिन्न और केंद्रीय घटक बन चुका है। विकसित भारत: सुरक्षा आयाम विषय-सार इस सम्मेलन की यही भावी और भू-आयामी दिशा दर्शाता है। इसमें वामपंथी उग्रवाद आतंकवाद-निरोध, आपदाप्रबंधन महिला सुरक्षा, साइबर-अपराध और फोरेसिक विज्ञान एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग जैसे विषयों पर गहन विचार-विमर्श हो रहा है। इन सभी क्षेत्रों में पिछले वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, और अब आवश्यकता है कि इन उपलब्धियों को एकीकृत कर एक ऐसे सुरक्षित भारत का निर्माण किया जाए, जो वैश्विक शक्ति बनने की अपनी आकांक्षा को सुरक्षा दृष्टि से भी पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके। यह सम्मेलन मूलतः एक ऐसे संवादात्मक मंच के रूप में विकसित हुआ है जहां राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े उच्चतम स्तर के निर्णयकर्ता पुलिस प्रशासन की वास्तविक चुनौतियों पर खुलकर चर्चा करते हैं। भारत जैसे विशाल, विविधतापूर्ण और निरंतर परिवर्तनशील देश में सुरक्षा चुनौतियाँ स्थिर नहीं हैं; वे लगातार रूप बदलती हैं, क्षेत्र विशेष के हिसाब से अपना अलग रूप लेती हैं और समय-समय पर तकनीकी, सामाजिक और भू-राजनीतिक स्वरूपों में विकसित हो रही रहती हैं। ऐसे वातावरण में पुलिस बलों के बीच अनुभवों का साझा होना, विभिन्न राज्यों के मॉडल का तुलनात्मक

और चुनौती दोनों ही विस्तृत हुई हैं। बाढ़, भूकंप, तूफान, भूस्खलन और शहरी आग जैसी घटनाओं में पुलिस बल न केवल राहत और बचाव कार्यों में प्रथम उत्तरदायक के रूप में कार्य करता है, बल्कि संघार समर्थन, कानून-व्यवस्था बनाए रखने, तथा भीड़-प्रबंधन में भी उसका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस सम्मेलन में यह विचार किया जा रहा है कि पूरे देश में आपदा-प्रबंधन के लिए पुलिस बलों को किस प्रकार आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और संसाधनों से लैस किया जाए, जिससे बड़ी त्रासदियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। इसका तैयार राष्ट्रीय स्तर पर एक समन्वित योजना की आवश्यकता है, जिसमें केंद्रीय पुलिस बलों और राज्य पुलिस के बीच स्पष्ट भूमिकाएँ और तकनीकी सहायता संरचना निर्धारित हों।

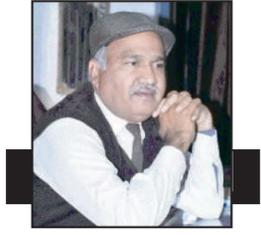
साथियों बात अगर हम महिला सुरक्षा को वर्तमान स्थिति में समझने की करें तो, 21वीं सदी में किसी भी आधुनिक और विकसित राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। भारत में महिला सुरक्षा के लिए अनेक योजनाएँ और तंत्र पहले से संचालित हो रहे हैं, लेकिन इस सम्मेलन का उद्देश्य इन योजनाओं का मूल्यांकन करना और एक समन्वित राष्ट्रीय स्थानीय सुरक्षा के समन्वय का उपयोग करना है। इसके साथ ही ड्रोन, उपग्रह निगरानी और एआई-आधारित पैटर्न विश्लेषण जैसे आधुनिक उपकरणों द्वारा उग्रवाद-निरोध को अधिक प्रभावी बनाने की विचार प्रक्रिया जा रहा है। आतंकवाद निरोध एक ऐसा क्षेत्र है, जिसे केवल जमीनी संघर्ष के रूप में नहीं देखा जा सकता। आधुनिक आतंकवाद अंतरराष्ट्रीय फंडिंग नेटवर्क, साइबर रिक्रूटमेंट, एनक्रिप्टेड कम्यूनिकेशन और ड्रोन-आधारित हमलों जैसे नए रूपों में उभर रहा है। भारत के सामने चुनौती यह है कि वह वैश्विक आतंकवाद के इन नए चेहरों से निपटने के लिए अपने सुरक्षा संसाधनों को तकनीकी और वैचारिक दोनों स्तरों पर आधुनिक बनाए। सम्मेलन में यह चर्चा हो रही है कि आतंकवाद विरोधी तंत्र को मजबूत करने के लिए सूचना-साझाकरण तंत्र (इंटेलिजेंस शेयरिंग) को और अधिक समन्वित, तेजी से क्रियाशील और प्रौद्योगिकी-सक्षम बनाया जाए। साथ ही, कठोरपंथ से लड़ने के लिए सामाजिक-मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते की आवश्यकता पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है।

साथियों बात अगर हम इसके समानांतर, आपदा प्रबंधन भी इस सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण विषय है इसको समझने की करें तो जिस प्रकार जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ा रहा है, उससे पुलिस और सुरक्षा प्रशासन की भूमिका

एआई न केवल अपराध की जांच में मदद करेगा बल्कि अपराध की भविष्यवाणी, ट्रैफिक प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण और आतंकवादी गतिविधियों के डेटा पैटर्न के विश्लेषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे पुलिस की कार्यकुशलता बढ़ेगी, जांच तेजी से पूरी होगी और न्याय व्यवस्था अधिक विश्वसनीय बनेगी। इस सम्मेलन का एक व्यापक उद्देश्य यह भी है कि पुलिस बलों के बीच परिक्षात्मक अवसर-चरणात्मक और कल्याणकारी चुनौतियों पर सामूहिक चर्चा हो। पुलिस व्यवस्था आज जिस तरह के दबावों में कार्य करती है, वह किसी भी लोकतांत्रिक देश की सुरक्षा और केंद्रीय धुरी है। लंबे कार्य घंटे, संसाधनों की कमी, तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव, आवास एवं परिवार कल्याण से जुड़ी समस्याएँ, और आधुनिक उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता न होना, ये सभी मुद्दे पुलिसिंग की गुणवत्ता पर प्रभाव डालते हैं। सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य एक ऐसा वातावरण बनाना है जहाँ पुलिस बलों को अत्याधुनिक उपकरण, बेहतर प्रशिक्षण, मानसिक स्वास्थ्य समर्थन, और पेशेवर उन्नयन के अवसर प्राप्त हों। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्तर पर एक दूरदर्शी सुरक्षा रोडमैप तैयार करने पर भी विचार किया जा रहा है। विकसित भारत की अवधारणा केवल आर्थिक समृद्धि से नहीं, बल्कि एक सुरक्षित समाज, सुव्यवस्थित कानून-व्यवस्था, सुचारु प्रशासन, और नागरिकों के अधिकारों की संपूर्ण सुरक्षा से ही संभव है। एक सुरक्षित भारत ही आर्थिक निवेश आकर्षित कर सकता है, वैश्विक व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण बना सकता है और सामूहिक सद्भाव को मजबूत कर सकता है। इस दृष्टि से यह सम्मेलन भविष्य के भारत की सुरक्षा संरचना को परिभाषित करने वाला एक निर्णायक अवसर है।

अतः अगर हम उपरोक्त विवरण का अध्ययन कर इसका विशेषण करें तो हम पाएंगे कि 60वां अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक सम्मेलन भारत की आंतरिक सुरक्षा यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह सम्मेलन न केवल वर्तमान चुनौतियों की समीक्षा कर रहा है, बल्कि सुरक्षा प्रशासन के लिए एक नए युग की शुरुआत का संकेत दे रहा है, एक ऐसा युग जिसमें तकनीक, वैज्ञानिक जांच, मानव-केंद्रित पुलिसिंग, सामाजिक संवेदनशीलता, राष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक सुरक्षा मानकों का सम्मिलन होगा। यह सम्मेलन एक सुरक्षित, विकसित और वैश्विक भारत की दिशा में भारत की सुरक्षा नीति को एक समन्वित, वैज्ञानिक और दूरदर्शी रूप देने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभा रहा है।

बच्चों के साहित्य विकास पत्रिकाओं की स्थायी आवश्यकता



डॉ. विजय गर्ग

एंटी-एजिंग प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक सर्जरी और तमाम ब्यूटी ट्रीटमेंट्स का बाज़ार खरबों रुपये का हो चुका है। कंपनियाँ लगातार यह संदेश देती हैं कि आप वैसे ही सुंदर नहीं हैं जैसा आपको होना चाहिए, और उनकी मदद से ही यह संभव है। कई समाजों में, खासकर महिलाओं के लिए, सुंदर दिखना सफलता और स्वीकार्यता का पैमाना बन गया है। स

आज की तेज गति वाली, डिजिटल दुनिया में, उच्च गुणवत्ता वाले बच्चों के साहित्य विकास पत्रिकाओं की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ये पत्रिकाएँ एक महत्वपूर्ण पुल के रूप में कार्य करती हैं, जो युवा पाठकों को साहित्य की खुशियों और विकासत्मक लाभों से जोड़ती हैं, तथा इन्हें ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करती हैं जो आकर्षक, सुलभ और उनकी आधुनिक संवेदनशीलता के अनुरूप हों। वे केवल पूरक पठन सामग्री नहीं हैं, बल्कि साक्षरता, आलोचनात्मक सोच, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और पढ़ने के आजीवन प्रेम को बढ़ावा देने में सक्रिय उपकरण हैं।

एक पत्रिका जो कल्पना को पोषित करती है
बच्चे स्वाभाविक रूप से सामान्य से परे दुनिया की कल्पना करते हैं। कहानियों, कविताओं, पहेलियों, लोक कथाओं और चित्रों से भरा एक अच्छी तरह से तैयार पत्रिका— जिज्ञासा के दरवाजे खोलती है। यह बच्चों को कल्पना करने, सपने देखने और नियमित शैक्षणिक सीखने की सीमाओं से परे सोचने के लिए प्रेरित करता है। साहित्य उन्हें सिखाता है कि प्रत्येक शब्द अपने भीतर एक ब्रह्मांड रखता है।
2। एक मजबूत भाषा नींव का निर्माण
नियमित रूप से पढ़ना बच्चों को नई शब्दावली, वाक्य संरचनाओं और भाषाई



पैटर्न के लिए उजागर करता है। विशेष रूप से युवा पाठकों के लिए डिजाइन की गई एक पत्रिका कर सकती है
आयु-उपयुक्त तरीकों से भाषा का परिचय दे
पढ़ने की समझ में सुधार करें लेखन कौशल को मजबूत करें अभिव्यंजक संचार को प्रोत्साहित करें पढ़ने की आदत विकसित करना जो बच्चे पढ़ते हैं वे सोचते हुए बड़े हो जाते हैं। पाठ्यपुस्तकों के विपरीत पत्रिकाएँ हल्की, अधिक आकर्षक और कम डराने वाली होती हैं। उनकी आकर्षक प्रकृति प्रत्याशा पैदा करती है। प्रत्येक नया अंक अन्वेषण का निमंत्रण बन जाता है:
एक ताजा कहानी एक नया पाठ एक नया हीरो एक नई चुनौती यह नियमित पढ़ने की आदत अनुशासन और बौद्धिक स्वतंत्रता का निर्माण करती है।
साक्षरता और संज्ञानात्मक विकास

क्षमता विकसित करने में मदद करता है।
शब्दावली और भाषा कौशल: साहित्यिक पत्रिकाएँ, विशेष रूप से, अच्छी तरह से लिखे गए गद्य और कविता के साथ समृद्ध हैं, जो बच्चों को विविध शब्दावली, जटिल वाक्य संरचनाओं और लेखन की विभिन्न शैलियों से परिचित कराती हैं। उनका उपयोग स्पष्ट रूप से साक्षरता कौशल सिखाने के लिए किया जा सकता है जैसे कहानी तत्वों की पहचान करना, मुख्य विचार और अनुमान लगाना।
डिजिटल युग में फोकस को बढ़ावा देना: डिजिटल विकर्षणों से भरे वातावरण में, एक भौतिक पत्रिका केंद्रित और जानबूझकर पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। परिवर्तमान पत्रिका की मूर्त प्रकृति, अक्सर आकर्षक चित्रों के साथ, बच्चे को एक ही कार्य पर केंद्रित रखती है, जिससे ध्यान और एकाग्रता कौशल का निर्माण करने में मदद मिलती है।
कल्पना और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाना
युवा दिमाग को आकार देने के लिए साहित्य मौलिक है, और पत्रिकाएँ इन आवश्यक कौशलों का अन्वेषण करने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं
उत्तेजक रचनात्मकता: एक साहित्यिक पत्रिका में पाए जाने वाले जीवंत चित्रण, आकर्षक पाठ और कल्पनाशील परिदृश्यों का संयोजन बच्चों को विभिन्न दुनियाओं में भ्रमण और नए पात्रों से मिलने की अनुमति देता है। यह कल्पनाशील खेल रचनात्मकता को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो जीवन के अन्य क्षेत्रों में समस्या-समाधान

संपादकीय

चिंतन-मगन



आज की तेज गति वाली, डिजिटल दुनिया में, उच्च गुणवत्ता वाले बच्चों के साहित्य विकास पत्रिकाओं की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ये पत्रिकाएँ एक महत्वपूर्ण पुल के रूप में कार्य करती हैं, जो युवा पाठकों को साहित्य की खुशियों और विकासत्मक लाभों से जोड़ती हैं, तथा इन्हें ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करती हैं जो आकर्षक, सुलभ और उनकी आधुनिक संवेदनशीलता के अनुरूप हों। वे केवल पूरक पठन सामग्री नहीं हैं, बल्कि साक्षरता, आलोचनात्मक सोच, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और पढ़ने के आजीवन प्रेम को बढ़ावा देने में सक्रिय उपकरण हैं।

एक पत्रिका जो कल्पना को पोषित करती है
बच्चे स्वाभाविक रूप से सामान्य से परे दुनिया की कल्पना करते हैं। कहानियों, कविताओं, पहेलियों, लोक कथाओं और चित्रों से भरा एक अच्छी तरह से तैयार पत्रिका— जिज्ञासा के दरवाजे खोलती है। यह बच्चों को कल्पना करने, सपने देखने और नियमित शैक्षणिक सीखने की सीमाओं से परे सोचने के लिए प्रेरित करता है। साहित्य उन्हें सिखाता है कि प्रत्येक शब्द अपने भीतर एक ब्रह्मांड रखता है।
2। एक मजबूत भाषा नींव का निर्माण
नियमित रूप से पढ़ना बच्चों को नई शब्दावली, वाक्य संरचनाओं और भाषाई

क्षमता विकसित करने में मदद करता है।
शब्दावली और भाषा कौशल: साहित्यिक पत्रिकाएँ, विशेष रूप से, अच्छी तरह से लिखे गए गद्य और कविता के साथ समृद्ध हैं, जो बच्चों को विविध शब्दावली, जटिल वाक्य संरचनाओं और लेखन की विभिन्न शैलियों से परिचित कराती हैं। उनका उपयोग स्पष्ट रूप से साक्षरता कौशल सिखाने के लिए किया जा सकता है जैसे कहानी तत्वों की पहचान करना, मुख्य विचार और अनुमान लगाना।
डिजिटल युग में फोकस को बढ़ावा देना: डिजिटल विकर्षणों से भरे वातावरण में, एक भौतिक पत्रिका केंद्रित और जानबूझकर पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। परिवर्तमान पत्रिका की मूर्त प्रकृति, अक्सर आकर्षक चित्रों के साथ, बच्चे को एक ही कार्य पर केंद्रित रखती है, जिससे ध्यान और एकाग्रता कौशल का निर्माण करने में मदद मिलती है।
कल्पना और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाना
युवा दिमाग को आकार देने के लिए साहित्य मौलिक है, और पत्रिकाएँ इन आवश्यक कौशलों का अन्वेषण करने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं
उत्तेजक रचनात्मकता: एक साहित्यिक पत्रिका में पाए जाने वाले जीवंत चित्रण, आकर्षक पाठ और कल्पनाशील परिदृश्यों का संयोजन बच्चों को विभिन्न दुनियाओं में भ्रमण और नए पात्रों से मिलने की अनुमति देता है। यह कल्पनाशील खेल रचनात्मकता को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो जीवन के अन्य क्षेत्रों में समस्या-समाधान

क्षमता विकसित करने में मदद करता है।
शब्दावली और भाषा कौशल: साहित्यिक पत्रिकाएँ, विशेष रूप से, अच्छी तरह से लिखे गए गद्य और कविता के साथ समृद्ध हैं, जो बच्चों को विविध शब्दावली, जटिल वाक्य संरचनाओं और लेखन की विभिन्न शैलियों से परिचित कराती हैं। उनका उपयोग स्पष्ट रूप से साक्षरता कौशल सिखाने के लिए किया जा सकता है जैसे कहानी तत्वों की पहचान करना, मुख्य विचार और अनुमान लगाना।
डिजिटल युग में फोकस को बढ़ावा देना: डिजिटल विकर्षणों से भरे वातावरण में, एक भौतिक पत्रिका केंद्रित और जानबूझकर पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। परिवर्तमान पत्रिका की मूर्त प्रकृति, अक्सर आकर्षक चित्रों के साथ, बच्चे को एक ही कार्य पर केंद्रित रखती है, जिससे ध्यान और एकाग्रता कौशल का निर्माण करने में मदद मिलती है।
कल्पना और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाना
युवा दिमाग को आकार देने के लिए साहित्य मौलिक है, और पत्रिकाएँ इन आवश्यक कौशलों का अन्वेषण करने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं
उत्तेजक रचनात्मकता: एक साहित्यिक पत्रिका में पाए जाने वाले जीवंत चित्रण, आकर्षक पाठ और कल्पनाशील परिदृश्यों का संयोजन बच्चों को विभिन्न दुनियाओं में भ्रमण और नए पात्रों से मिलने की अनुमति देता है। यह कल्पनाशील खेल रचनात्मकता को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो जीवन के अन्य क्षेत्रों में समस्या-समाधान

तकनीक से जीवन और गरिमा की रक्षा

डॉ विजय गर्ग
भारत की चमकीली सड़कों, ऊंची इमारतों और 'स्मार्ट' शहरों की योजनाओं के पीछे एक कड़वी सच्चाई छिपी है। देश के कई हिस्सों में आज भी हजारों लोग सीवर और नालियों में उतरकर अपने हाथों से सफाई करने को मजबूर हैं। ऐसे में कई बार जहरीली गैस की वजह से सफाई कर्मियों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। यह पेशा नहीं, बल्कि समाज में असमानता और भेदभाव का जीवंत प्रतीक है। देश में कभी-कभी सफाई कर्मचारियों को वर्ष में दो-चार मौकों पर किसी सरकारी समारोह में सम्मानित किया जाता है। ऐसा करके यह दिखाया जाता है कि सरकार उनको महान और योगदान के महत्त्व को मानती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कुछ मिनटों का यह सम्मान उनके लिए स्थायी सुरक्षा, गरिमा या बेहतर जीवन की गारंटी नहीं देता है। असली गरिमा तो तब आती है, जब उनके काम करने के तरीके में बदलाव होगा, उन्हें खतरनाक और अमानवीय परिस्थितियों में नहीं, बल्कि सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से काम करने और जीने का अवसर मिलेगा।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' तकनीक का इस्तेमाल इसमें अहम भूमिका निभा सकता है।
हर वर्ष देश में सैकड़ों सफाई कर्मचारी सीवर के गड्ढों और नालियों में दम घुटने, जहरीली गैस या कट लपने से अपनी जान गंवा देते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के के अनुसार, वर्ष 2018 से 2023 के बीच चार सौ से अधिक लोगों की मृत्यु सीवर की सफाई के दौरान हुई। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का मानना है कि यह संख्या वास्तविकता से कहीं कम है, क्योंकि कई मौतें दर्ज नहीं हो पातीं। इन मृतकों में आमतौर पर दलित समुदाय लोग होते हैं, जिन्हें सदियों से इस कार्य में धकेला गया है। यह स्थिति हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में उस भारत में रह रहे हैं, जिसने अपने संविधान में समानता और गरिमा का वादा किया था। भारत का संविधान हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और गरिमा का अधिकार देता है अनुच्छेद 14 कहता है कि सभी नागरिक कानून के समान हैं। अनुच्छेद-17 में अस्पृश्यता को समाप्त किया और इसे किसी भी रूप में लागू करने या मानने को अपराध बताया गया है। वहीं अनुच्छेद-21 हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसका अर्थ केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीना भी है। यही संविधान का नैतिक आधार है।

डॉ विजय गर्ग
युवा है वर्ष 2013 में केंद्र सरकार ने 'हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारियों के रोजगार प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम' लागू किया। इस कानून का उद्देश्य हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना तथा इसे जुड़े लोगों को वैकल्पिक रोजगार, शिक्षा और सम्मानजनक जीवन देना था। मगर यह दुखद है कि कानून बनने के बावजूद यह अमानवीय प्रथा अब भी जारी है। इसका कारण केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि सामाजिक मानसिकता की गहरी जड़ें हैं, जो सफाई के काम को एक खास वर्ग से जोड़कर देखती हैं। जब भी किसी इलाके में सीवर की नाली जाम होती है, तो मशीनों की बजाय किसी सफाई कर्मी को नीचे भेजा जाता है। वह भी बिना सुरक्षा उपकरण बिना प्रशिक्षण और बिना जीवन की गारंटी के। अब समय आ गया है कि इस समस्या को केवल कानून या नैतिकता से नहीं, बल्कि विज्ञान और तकनीक की मदद से भी समाप्त करने के प्रयास किए जाएं। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग है। यह वह तकनीक है, जो मशीनों को मानव जैसी समझ, निर्णय क्षमता और सोचने की योग्यता देती है। इसका सही उपयोग हाथ से मैला साफ करने जैसी अमानवीय प्रथा को खत्म करने में क्रांतिकारी भूमिका निभा सकता है।
भारत में भी अब कृत्रिम मेथा पर आधारित रोबोट विकसित किए गए हैं, जो सीवर की नालियों में उतरकर सफाई कर सकते हैं। यह रोबोट कैमरे एवं सेंसर की मदद से गंदगी और रुकावट का पता लगाता है तथा मशीनों हाथों से सफाई करता है। इस तकनीक का प्रयोग अब तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, लखनऊ और लॉगा जैसे शहरों में किया जा रहा है। इससे न केवल लोगों की जानें बची हैं, बल्कि यह भी सिद्ध हुआ है कि सफाई गरिमा के साथ की जा सकती है। दरअसल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी प्रणाली सीवर की नालियों में लगे सेंसर के माध्यम से पानी का प्रवाह, गैस का स्तर और दबाव को जानकारी एकर करती है। इन आंकड़ों का विश्लेषण मशीन लर्निंग प्रणाली द्वारा किया जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उल का उपयोग केवल सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से सफाई कर्मचारियों को प्रशिक्षण और पुनर्वास के अवसर भी मिल सकते हैं। उन्हें मशीन संचालन, डेटा विश्लेषण और तकनीकी प्रबंधन जैसे कार्यों में प्रशिक्षित किया जा सकता है, ताकि उनका जीवन सुरक्षित और सम्मानजनक बन सके।
दुनिया के कई देशों ने यह साबित कर दिया है कि सीवर की सफाई इंसान की जान जोखिम में डाले बिना

डॉ विजय गर्ग
भारत की वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या साल 2036 तक बढ़कर लगभग 23 करोड़ हो जाएगी
डॉ विजय गर्ग
अनुमान है कि भारत की वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या साल 2036 तक बढ़कर लगभग 23 करोड़ हो जाएगी, जो कुल जनसंख्या का लगभग 15 फीसद होगा। हिमाचल प्रदेश और पंजाब सहित दक्षिणी राज्यों में वृद्धों की आबादी अधिक है, तथा 2036 तक क्षेत्रीय असमानताएँ बढ़ने की संभावना है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु अधिनियम, नीतियाँ विकसित एवं कार्यान्वित करता है।
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 और बाद में संशोधित माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण (संशोधन) अधिनियम, 2019 कानूनी रूप से बच्चों और उत्तराधिकारियों को माता-पिता को भरण-पोषण प्रदान करने के लिए बाध्य करता है।
भारत तेजी से जनसांख्यिकीय परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, और अनुमान है कि वृद्ध जनसंख्या (60 वर्ष और उससे अधिक) साल 2011 के 10 करोड़ से बढ़कर 2036 तक दो गुने से भी ज्यादा यानी 23 करोड़ हो जाएगी। यह परिवर्तन दर्शाता है कि साल 2036 तक, लगभग हर सात में से एक भारतीय 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का होगा, जो देश की जनसंख्या संरचना में एक बुनियादी बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। इस परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, भारत ने घटती प्रजनन दर और बढ़ती जीवन प्रत्याशा दरों से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए कई नीतियाँ, कार्यक्रम और कानूनी प्रावधान अपनाए हैं।
बुजुर्गों की जरूरतों को पूरा करने का महत्त्व बेहतर पोषण और स्वास्थ्य सेवा में भारत में लोगों को लंबी उम्र जीने में मदद की है, लेकिन इससे बढ़ती उम्र के साथ नई चुनौतियाँ और अवसर भी सामने आते हैं। सकारात्मक और गुणवत्तापूर्ण

डॉ विजय गर्ग
भारत की वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या साल 2036 तक बढ़कर लगभग 23 करोड़ हो जाएगी
डॉ विजय गर्ग
अनुमान है कि भारत की वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या साल 2036 तक बढ़कर लगभग 23 करोड़ हो जाएगी, जो कुल जनसंख्या का लगभग 15 फीसद होगा। हिमाचल प्रदेश और पंजाब सहित दक्षिणी राज्यों में वृद्धों की आबादी अधिक है, तथा 2036 तक क्षेत्रीय असमानताएँ बढ़ने की संभावना है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु अधिनियम, नीतियाँ विकसित एवं कार्यान्वित करता है।
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 और बाद में संशोधित माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण (संशोधन) अधिनियम, 2019 कानूनी रूप से बच्चों और उत्तराधिकारियों को माता-पिता को भरण-पोषण प्रदान करने के लिए बाध्य करता है।
भारत तेजी से जनसांख्यिकीय परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, और अनुमान है कि वृद्ध जनसंख्या (60 वर्ष और उससे अधिक) साल 2011 के 10 करोड़ से बढ़कर 2036 तक दो गुने से भी ज्यादा यानी 23 करोड़ हो जाएगी। यह परिवर्तन दर्शाता है कि साल 2036 तक, लगभग हर सात में से एक भारतीय 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का होगा, जो देश की जनसंख्या संरचना में एक बुनियादी बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। इस परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, भारत ने घटती प्रजनन दर और बढ़ती जीवन प्रत्याशा दरों से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए कई नीतियाँ, कार्यक्रम और कानूनी प्रावधान अपनाए हैं।
बुजुर्गों की जरूरतों को पूरा करने का महत्त्व बेहतर पोषण और स्वास्थ्य सेवा में भारत में लोगों को लंबी उम्र जीने में मदद की है, लेकिन इससे बढ़ती उम्र के साथ नई चुनौतियाँ और अवसर भी सामने आते हैं। सकारात्मक और गुणवत्तापूर्ण

भविष्य का भय

भारत की वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या साल 2036 तक बढ़कर लगभग 23 करोड़ हो जाएगी
डॉ विजय गर्ग
अनुमान है कि भारत की वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या साल 2036 तक बढ़कर लगभग 23 करोड़ हो जाएगी, जो कुल जनसंख्या का लगभग 15 फीसद होगा। हिमाचल प्रदेश और पंजाब सहित दक्षिणी राज्यों में वृद्धों की आबादी अधिक है, तथा 2036 तक क्षेत्रीय असमानताएँ बढ़ने की संभावना है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु अधिनियम, नीतियाँ विकसित एवं कार्यान्वित करता है।
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 और बाद में संशोधित माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण (संशोधन) अधिनियम, 2019 कानूनी रूप से बच्चों और उत्तराधिकारियों को माता-पिता को भरण-पोषण प्रदान करने के लिए बाध्य करता है।
भारत तेजी से जनसांख्यिकीय परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, और अनुमान है कि वृद्ध जनसंख्या (60 वर्ष और उससे अधिक) साल 2011 के 10 करोड़ से बढ़कर 2036 तक दो गुने से भी ज्यादा यानी 23 करोड़ हो जाएगी। यह परिवर्तन दर्शाता है कि साल 2036 तक, लगभग हर सात में से एक भारतीय 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का होगा, जो देश की जनसंख्या संरचना में एक बुनियादी बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। इस परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, भारत ने घटती प्रजनन दर और बढ़ती जीवन प्रत्याशा दरों से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए कई नीतियाँ, कार्यक्रम और कानूनी प्रावधान अपनाए हैं।
बुजुर्गों की जरूरतों को पूरा करने का महत्त्व बेहतर पोषण और स्वास्थ्य सेवा में भारत में लोगों को लंबी उम्र जीने में मदद की है, लेकिन इससे बढ़ती उम्र के साथ नई चुनौतियाँ और अवसर भी सामने आते हैं। सकारात्मक और गुणवत्तापूर्ण

डब्ल्यूपीएल ऑक्शन: जहाँ पैसा नहीं, सपने अनुबंध हुए

हॉल अचानक एक अनकहे, जलते हुए आगोश में बदल गया। हर कोना, हर चेहरा, हर निगाह जैसे उस क्षण के लिए सजना हो गया था। बल दिल्ली के उस हॉल में हथौड़ा तीसरी बार गिरा बज्ज एडम्स की आवाज गुंज उठी— "सोल्ट! श्री क्रोर ट्वेंटी लख्स टू यूनिवर्सिटी!", तो ऐसा लगा जैसे पूरे हिंदुस्तान की साँस एक ही क्षण में थम गई हो। 3.20 करोड़। सिर्फ एक आंकड़ा नहीं; यह एक सपना, एक संघर्ष, और एक गाँव की बेटी की असंभवता की जीत थी। वही लड़की, जिसकी बचपन की रातें उजाले से वंचित, संघर्ष और साधारण सपनों के बीच बीतीं, आज तीन करोड़ बीस लाख रुपये की अनुबंध राशि लेकर मैदान पर खड़ी थी। तालियाँ नहीं बजीं; दिलों की धड़कनें बजीं। यह कोई विमल-सुप्रीमिअर लीग (डब्ल्यूपीएल) ऑक्शन का क्षण नहीं था; यह सपनों की जीत की चोख थी, यह एक नया युग की शुरुआत थी, यह भारत की महिला क्रिकेट में क्रांति का गर्जन था।
दीपति शर्मा ने सिर्फ़ रिकॉर्ड नहीं बनाया, उसने एक पुरानी, गहरी और जड़ जमा चुकी मानसिकता को हमेशा के लिए दफन कर दिया। वही मानसिकता जो सालों से चुपचाप कानों में फुसफुसाती रही थी— "लड़कियाँ खेलेंगी तो क्या होगा? शादी-ब्याह में क्या काम आएगा?"— उसकी हर फुसफुसाहट को दीपति ने 3.20 करोड़ के शक्तिशाली, गरजते हुए श्रौंडे की गूँज से हमेशा के लिए दबा दिया। स्मृति में घाना का 3.40 करोड़ का रिकॉर्ड तीन सालों तक अडिगा और अटल था। दीपति ने उसे केवल इतना करीब पहुँचाया कि अब हर लड़की के मन में एक सपना, एक आँसू और निर्भीक विश्वास जाग उठा— "मेरा भी नंबर आ सकता है, और मैं भी इतिहास रच सकती हूँ।"
लेकिन सच्चाई यही है कि यह चमक अभी केवल सतही परत तक ही सीमित है। टॉप की दस खिलाड़ी कुल मिलाकर पंद्रह-बीस करोड़ कमा चुकी हैं, जबकि नब्बे में से शेष खिलाड़ी दस, बीस या तीस लाख की सीमित राशि में ही सिमट गए हैं। पैसा आया, यह सच है, लेकिन अभी यह केवल कुछ चमकते सितारों तक ही सीमित रहा। नीचे की पायदान पर खड़ी वह लड़की, जो आज दीपति की उपलब्धियों को देखकर अपने सपनों को पंख दे रही है, उसके लिए अवसर का दरवाजा अभी भी आधा खुला है। और सवाल वही पुराना, वही चुनौतीपूर्ण है— क्या यह क्रिकेट का बूम पूरे खेल के कोने-कोने तक फैल पाएगा, या केवल ऊपरी मलाई में ही फँसकर रह जाएगा?
फिर भी, एक सत्य निर्विवाद है— दीपति ने वह काँच की छत तोड़ दी जो दशकों से भारतीय महिला क्रिकेट पर भारी पड़ी थी। अब जिम्मेदारी और दबाव दुगुना हो गया है। हर गेंद पर निगाहें टिकी हैं, हर रन पर

स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को प्राथमिकता देनी चाहिए, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों के लिए। जनसांख्यिकीय रूझान
भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या प्रक्षेपण रपट जुलाई 2020 में जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह (टीसीपीपी) द्वारा बनाई गई थी। इसमें वृद्ध लोगों की आबादी का अनुपात कैसे बदल रहा है और भविष्य के लिए क्या अनुमान हैं, इसका जिक्र है। रपट के अनुसार, भारत की बुजुर्ग आबादी 2036 तक 23 करोड़ तक पहुंच जाएगी, जो व्यापक प्रभावों के साथ एक गहन सामाजिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है। देश जनसंख्या की उम्र बढ़ने में महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय असमानताओं को प्रदर्शित करता है और यह जनसांख्यिकीय बदलाव पूरे देश में एक समान नहीं है। केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पहले से ही विकसित देशों की तरह बुजुर्गों की संख्या काफी ज्यादा है। केरल की बुजुर्ग आबादी 2011 के 13 फीसद से बढ़कर 20

बदलती विश्व-त्यवस्था और जी-20 की चुनौती : बहुध्रुवीयता के बीच भारत की उभरती वैश्विक भूमिका

भू-राजनीतिक तनावों, आर्थिक अस्थिरता और नेतृत्व संकट से जुड़ते जी-20 में भारत का वैश्विक दक्षिण की आवाज के रूप में उदय जी-20 वैश्विक आर्थिक समन्वय का सबसे प्रभावी मंच है, परन्तु आज यह गहरे भू-राजनीतिक विभाजन, महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा, आर्थिक असमानताओं और नेतृत्व संकट जैसी कई चुनौतियों से घिरा है। इससे समूह की प्रसंगिकता एवं क्षमता दोनों पर प्रश्नचिह्न लग गए हैं। ऐसे जटिल समय में भारत ने स्वयं को वैश्विक दक्षिण की सशक्त आवाज के रूप में स्थापित किया है—अफ्रीकी संघ की सदस्यता सुनिश्चित करने से लेकर समावेशी विकास, शांति-आधारित कूटनीति और दक्षिण-दक्षिण सहयोग के नए मॉडल प्रस्तुत करने तक। फिर भी वैश्विक शक्ति-संघर्ष भारत की प्रभाव क्षमता को सीमित करते हैं और जी-20 की कार्यकुशलता को प्रभावित करते हैं।
- डॉ प्रियंका सौरभ
विश्व-राजनीति वर्तमान समय में गहरे परिवर्तनों से गुजर रही है। महाशक्तियों के बीच अविश्वास, क्षेत्रीय युद्ध, आर्थिक संकट, तकनीकी

वर्चस्व की होड़, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे और वैश्विक संस्थाओं में घटती प्रभावशीलता ने विश्व-व्यवस्था को अस्थिर बना दिया है। ऐसे दौर में जी-20 को विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करने का सबसे महत्वपूर्ण मंच है, स्वयं को अभूतपूर्व चुनौतियों के बीच पाता है। समूह की प्रभावशीलता पर बढ़ते संदेह मात्र इसके कार्य-तंत्र से उत्पन्न नहीं हुए, बल्कि यह बदलती विश्व-स्थिति और बहुध्रुवीयता के असंतुलन का प्रत्यक्ष परिणाम है।
जी-20 की सबसे गंभीर चुनौती गहराता हुआ भू-राजनीतिक विभाजन है। यूक्रेन क्षेत्र में चल रहा युद्ध, पश्चिम एशिया की अस्थिरता, प्रशांत क्षेत्र में टकराव, बड़े देशों के बीच तकनीकी एवं आर्थिक प्रतिस्पर्धा, तथा बढ़ते प्रतिबंधों ने समूह की सहमति-निर्माण क्षमता को कमजोर बनाया है। कई बार ऐसे परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि साझा घोषणा-पत्र निकालना भी कठिन हो जाता है। उदाहरणस्वरूप, जोहान्सबर्ग बैठक में केवल अत्यंत सामान्य रूप से 'स्थायी एवं न्यायपूर्ण शांति' की अपील की गई, क्योंकि सदस्यों के दृष्टिकोण आपस में टकराते रहे। यह स्थिति दिखाती है कि वैश्विक मुद्दों पर सामूहिक स्वर तैयार करना कितना कठिन हो चुका है।

महाशक्तियों के व्यक्तिगत हित कई बार समूह के सामूहिक हितों पर भारी पड़ जाते हैं। इससे रउबटूर—अर्थात् "मैं हूँ क्योंकि हम हैं"—जैसी साझी जिम्मेदारी की मूल भावना क्षीण होती जा रही है। कुछ प्रमुख देशों द्वारा सम्मेलन से दूरी बनाना, या महत्वपूर्ण विमर्शों में भागीदारी में अनिच्छा दिखाना, समूह की विश्वसनीयता को कमजोर करता है। इससे जी-20 उस भूमिका को नहीं निभा पाता जिसके लिए यह बनाया गया था—यानी वैश्विक समस्याओं के समाधान हेतु सामूहिक एवं समन्वित प्रयास।
इसके साथ ही आर्थिक असमानता जी-20 के सामने एक और महत्वपूर्ण चुनौती है। विकसित और विकासशील देशों के बीच आय, तकनीक, स्वास्थ्य-सुविधाएँ, कौशल, ऊर्जा स्रोतों और जलवायु वित्त में बढ़ती खाई ने समूह के भीतर संतुलन को प्रभावित किया है। वैश्विक श्रॉण संकट, विकासशील देशों पर बढ़ता आर्थिक दबाव, मंदी का खतरा, और असमान व्यापार-संरचना मिलकर ऐसे परिदृश्य का निर्माण करते हैं जिसमें साझा नीति बनाना कठिन हो जाता है। ऐसे समय में समूह को जिस सशक्त नेतृत्व और सहयोग की आवश्यकता है, वह कई बार अनुपस्थित दिखाई देता है।
इन जटिल परिस्थितियों के बीच भारत ने जी-

20 में अत्यंत सकारात्मक, समावेशी और संतुलनकारी भूमिका निभाई है। भारत ने न केवल वैश्विक दक्षिण की चिंता और अपेक्षाओं को केन्द्र में रखा, बल्कि ऐसे दोष कदम को गटजोड़ को। यह विश्व दीर्घकालिक प्रभाव दिखाई देता है। भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि अफ्रीकी संघ को जी-20 की स्थायी सदस्यता दिलाना रही। यह निर्णय न केवल ऐतिहासिक था, बल्कि उन विकासशील देशों की पुरानी मांग को भी पूरा करता था जिन्हें वैश्विक निर्णय-प्रक्रिया में बराबरी का स्थान नहीं मिलता रहा। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि भारत वैश्विक व्यवस्था को अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
भारत ने विकासशील देशों की वास्तविक आवश्यकताओं पर आधारित कई व्यावहारिक एवं मापनीय पहलों को आगे बढ़ाया। डिजिटल सर्वजनिक संरचना का मॉडल, स्वास्थ्य-सुरक्षा व्यवस्था, कौशल विकास, ग्रामीण एवं कृषि नवाचार, मत्स्य प्रबंधन, पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण, आपदा प्रबंधन में सहयोग, और उपग्रह आंकड़ों का साझा उपयोग—ये सभी पहलें विकासशील देशों की आवश्यकताओं से सीधे जुड़ी हैं। विशेषकर अफ्रीकी कौशल युद्ध योजनाएं जैसी पहलें लाखों युवाओं के लिए अवसरों का मार्ग

खोलती हैं।
भारत ने वैश्विक सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया, विशेषकर आतंकवाद और नशीली दवाओं के गटजोड़ को। यह विश्व लंबे समय से वैश्विक विमर्श में अपेक्षित महत्त्व नहीं पाता रहा था। भारत ने इसके विरुद्ध कठोर और समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इसके साथ ही न्यायपूर्ण ऊर्जा परिवर्तन, जलवायु वित्त, सतत विकास, तकनीक की समान उपलब्धता और खाद्य-सुरक्षा जैसे विषयों पर भी भारत ने विकासशील देशों की सामूहिक आवाज को मजबूत किया।
हालाँकि भारत की भूमिका अत्यंत प्रभावशाली रही है, फिर भी इसकी कुछ सीमाएँ स्पष्ट रूप से सामने आती हैं। महाशक्तियों के बीच चल रहे तीव्र संघर्षों के बीच भारत सभी पक्षों को एकजुट नहीं कर सका। प्रमुख देशों की अनुपस्थिति को भारत रोक नहीं पाया, न ही यह सुनिश्चित कर सका कि सभी देश साझा घोषणा-पत्र में कठोर रुख अपनाएँ। अंततः भारत पर अपेक्षित कठोर निंदा का शामिल न हो पाना भारत के लिए निराशाजनक था। इसी प्रकार भारत की कई विकास सम्बन्धी पहलें सभी देशों की समान रुचि और समर्थन प्राप्त नहीं कर पाईं, क्योंकि प्रत्येक देश की प्राथमिकताएँ भिन्न

होती हैं।
वैश्विक दक्षिण के भीतर भी कई बार मतभेद देखने को मिलते हैं, जिससे समग्र एजेंडा कमजोर पड़ता है। भारत की कूटनीति संतुलनकारी अवश्य है, परन्तु महाशक्तियों के कठोर और प्रतिस्पर्धी रुख के बीच इसकी प्रभाव सीमा सीमित हो जाती है।
फिर भी यह निर्विवाद है कि आज वैश्विक दक्षिण का ऐसा कोई और देश नहीं है जो भारत जैसी व्यापक, संतुलित, विश्वसनीय और दूरदर्शी भूमिका निभा सके। भारत ने जी-20 के मंच को नई ऊर्जा दी है, वैश्विक दक्षिण के हितों को उचित समान दिलाया है, और वैश्विक शासन में समावेशिता की नई परिभाषा प्रस्तुत की है।
अंततः, जी-20 की भविष्य की सफलता उसके सदस्यों की सामूहिकता की भावना, परस्पर विश्वास, और साझा उत्तरदायित्व को पुनर्जीवित करने पर निर्भर करेगी। यदि समूह रउबटूर—यानी साझा मानवता और साझा दायित्व—के सिद्धांत को पुनः अपनाता है, तो यह वैश्विक चुनौतियों से प्रभावी रूप से निपट सकता है। भारत ने इस दिशा में मजबूत नींव रखी है, और आने वाले समय में उसकी भूमिका और अधिक निर्णायक रूप से उभर सकती है।



प्लाइ एस की अवैध परिवहन तुरंत बंद हो, प्रशासनिक कार्रवाई स्वागतोग्य - प्रदेश अध्यक्ष रा.कां. पा

जनता से भी भरपूर सहयोग की अपील, एकजुटता ही समस्या का समाधान- डॉ राजकुमार यादव



परिवहन विशेष न्यूज

सुंदरगढ़ / राउरकेला - सुंदरगढ़ जिले में पावर प्लांटों से निकल रही प्लाई एस का अवैध परिवहन और अनियंत्रित ढंग से इधर-उधर डंपिंग, जिले के पर्यावरण, कृषि भूमि और जनस्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा बन चुका है। बीती रात सड़क किनारे प्लाई एस फेंकने की सूचना पर सुंदरगढ़ एसपी अमृत पाल कौर द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई में 6 ट्रकों को जब्त किया गया, जो इस समस्या की भयावहता को स्पष्ट करता है। इसी बीच, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी

के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजकुमार यादव ने प्लाई एस के अवैध परिवहन व अनियंत्रित निष्पादन पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि—
“प्लाई एस माफिया प्रशासनिक नियमों को धता बताते हुए रात के अंधेरे में जिले को प्रदूषण के खतरनाक दलदल में धकेल रहे हैं। कृषि भूमि, नदी क्षेत्रों और आबादी वाले इलाकों में इस तरह की अवैध डंपिंग न सिर्फ पर्यावरण पर हमला है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से भी खिलवाड़ है। सरकार और प्रशासन को ऐसे माफियाओं के

खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करनी होगी।
डॉ. यादव ने जिला प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि यह मुहिम और सख्त होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि—
“यदि प्लाई एस का अवैध परिवहन और डंपिंग नहीं रुकी, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जनआंदोलन खड़ा करने के लिए बाध्य होगी। जनता के जीवन और स्वास्थ्य से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

उन्होंने जिला प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पुलिस और संबंधित विभागों से समन्वित अभियान चलाकर प्लाई एस माफियाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की।
सुंदरगढ़ जिला लंबे समय से प्रदूषण की मार झेल रहा है—एसे में प्लाई एस का अनियंत्रित फैलाव एक और बड़ी चुनौती बन गया है। प्रशासन द्वारा 6 ट्रकों की जब्त यह संकेत है कि अवैध कारोबार किस स्तर पर फल-फूल रहा था।

झारखंड में पत्ता चुनने गयी 18 वर्षिया फूलो आईडी विस्फोट में मृत, दो घायल

ब्लास्ट में 20 फीट ऊपर उठी फूलो की मौत हो गयी

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

याँबासा, झारखंड के सांठडा जंगल में एक बार फिर आईडी ब्लास्ट हुआ है, इसमें एक युवती की मौत हो गयी है और 2 अन्य महिलाएं घायल हुईं हैं, 18 साल की फूलो धनवार की मौत हो गयी, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विस्फोट के बाद फूलो का शरीर 20 फीट ऊपर तक उड़ गया, इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने अफ़स-अफ़सरी मच गयी, शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे मनोरथपुर प्रखंड के जराइकटा थाना क्षेत्र के सांठडा जंगल में कोलंबोना गांव के पास के लेबरगढ़ा जंगल में बरखंडियाओं द्वारा बिछाये गये आईडी में ब्लास्ट हो गया, इस विस्फोट में कोलंबोना गांव की फूलो धनवार की मौत हो गयी, ब्लास्ट में 2 महिला घायल हुईं हैं, उन्हें देर शाम इलाज के लिए मनोरथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया घायल महिलाओं में कोलंबोना गांव की बिबसी धनवार (35) और साल्ती कांडुतना (32) शामिल हैं, साल्ती लासलोर पंचायत की गुरिद्या बिबसा कंडुतना की बहन हैं, उसे कई जगह गंभीर घोटें लगीं हैं, उसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है घायलों और अन्य लोगों ने बताया कि गांव के दर्जन भर लोग रोज की तरह शुक्रवार सुबह 7 बजे जंगल से पत्ता चुनने गये थे, करीब 2 बजे वे लोग घर लौट रहे थे,



विधायक डॉ अजय गुप्ता ने नया आम आदमी क्लिनिक बनाने का किया उद्घाटन: कहा, क्लिनिकों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही

अमृतसर, 28 नवंबर (साहिल बेरी)

केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉ अजय गुप्ता ने आज कटरा मोती राम आर्य समाज स्कूल के सामने नया आम आदमी क्लिनिक बनवाने का उद्घाटन किए। विधायक डॉ अजय गुप्ता ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा लगातार आम आदमी क्लिनिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब में 900 के करीब आम आदमी क्लिनिकों की संख्या पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि अमृतसर जिले



के कुल 74 से अधिक आम आदमी क्लिनिक चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लगातार लोगों तक पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी क्लिनिक में गर्भवती माताओं की

जाँच, उपचार, दवाइयाँ, एंटी-रेबीज वैक्सीन, नियमित प्रबंधन और अन्य सभी बीमारियों का मुफ्त इलाज करवाया जाता है। इसके साथ-साथ क्लिनिक में टेस्ट भी मुफ्त किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन

हजारों की संख्या में लोग इसका लाभ ले रहे हैं। इस अवसर पर मनदीप सिंह मोगा, विशाल भट्टी, ऋषि कपूर, चरणजीत सिंह, अजय न्यूल, गुरदास सिंह और भारी संख्या में क्षेत्र के लोग मौजूद थे।

वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वल्ला में लगाया हैल्थ चैकअप और खूनदान कैंप



अमृतसर 28 नवंबर (साहिल बेरी)

निगम कमीश्नर बिक्रमजीत सिंह शेरीगल के दिशा-निर्देश अनुसार नगर निगम और लार्सन एंड टूबो कंपनी द्वारा श्री गुरु रामदास इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस एंड रिसर्च तथा अमृतसर मैडिकल कॉलेज के सहयोग से नगर निगम और लार्सन एंड टूबो कंपनी द्वारा अमृतसर बल्क वाटर स्पलाई स्कीम के तहत

वल्ला में बनाए जा रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए डेंटल चैकअप, जर्नल हैल्थ चैकअप कैंप के साथ-साथ रक्तदान कैंप लगाया गया। जिसमें डा. लाविया कौर और डा. कंचनजीत कौर और उनकी टीम द्वारा कैंप में मौजूद लोगों के दातों की जांच और स्वास्थ्य की जांच के साथ-साथ बल्डप्रेसर और शूगर की भी जांच की गई। कैंप के



दौरान सरकारी मैडिकल कॉलेज की टीम द्वारा रक्तदान कैंप का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर एक्सईएन सुनील महाजन ने कहा कि किसी भी प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए जरूरी है कि प्रोजेक्ट में काम करने वाले कर्मचारियों का स्वास्थ्य रहे। इसीलिए इस कैंप का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 100 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई और

जरूरत के अनुसार दवाईयाँ भी दी गईं और साथ ही लगभग 13 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। उनके द्वारा कैंप में आए हुए डाक्टरों और मैडिकल टीम को धन्यवाद किया गया। इस मौके पर डा. सुमित अरोड़ा, कंचनजीत सिंह, हरप्रीत सिंह, भरत चक्रवर्ती, हिमार्शु वलिया, बनाप्रिया, आदि भी उपस्थित थे।

करमजीत सिंह रिटू ने मजीठा - वेरका बाईपास से सनसिटी तक प्रीमिक्स से सड़के बनवाने का किया उद्घाटन



अमृतसर, 28 नवंबर (साहिल बेरी)

इंफ्रामेंट ट्रस्ट अमृतसर के चेयरमैन एवं उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के इंचार्ज करमजीत सिंह रिटू ने मजीठा - वेरका बाईपास से सनसिटी तक प्रीमिक्स से सड़के बनवाने का उद्घाटन किया। रिटू ने कहा कि इस सड़क के निर्माण से गुरुदास बाबा श्रीचंद, माता महाकाली मंदिर और 10 से अधिक कॉलोनीयों के निवासियों को सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने उनको उत्तरी विधानसभा

क्षेत्र की सेवा करने का मौका दिया हुआ है। जिस पर वह क्षेत्र के लोगों की सेवा करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तरी विधानसभा के प्रत्येक क्षेत्र के विकास करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। उन्होंने कहा कि पिछले तीन महीनों में सड़के और गलियां बनवाने के कार्य लगातार जारी हैं।

रिटू ने कहा कि उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के निवासियों से किए गए हर वादे को समय पर पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों का निर्माण आधुनिक तकनीक से सभी

प्रकार के सर्वेक्षणों के बाद पूरा किया जा रहा है और सड़के अत्यंत उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी सड़क अधूरी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तरी क्षेत्र में विकास को रफ्तार को रकने नहीं दिया जाएगा और हर गली-मोहल्ले तक विकास पहुंचाया जा रहा है।

करमजीत सिंह रिटू ने कहा कि इंफ्रामेंट ट्रस्ट अमृतसर द्वारा शहर के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंफ्रामेंट ट्रस्ट

अपनी प्रत्येक स्कीम पर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट द्वारा आने वाले दिनों में लगभग 5.4 करोड़ रुपये के विकास कार्य शुरू करवाने जा रही हैं। जिससे मुख्य तौर पर रोजीत एवेन्यू का क्षेत्र उच्च स्तरीय बनाने लगेगा। उन्होंने कहा कि लोगों के बीच जाकर उसकी समस्याओं को सुनकर उनका पहलू के आधार पर हल भी करवाया जाता है। इस अवसर पर सीनियर डिप्टी मेयर प्रियंका शर्मा, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स और भारी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद थे।



आदर्श ग्रुप चिटफंड धोखाधड़ी मामला: ईडी ने दो लोगों के घरों पर छापेमारी की

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओडिशा

भूबनेश्वर : कटक जिले के निश्चितकोइली इलाके के नटेकाई और रामकृष्णपुर में ED ने दो लोगों के घरों पर छापा मारा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज सुबह-सुबह नटेकाई ग्राम पंचायत के विजय राउत और रामकृष्णपुर पंचायत के जितेंद्र ओझा के घरों पर छापा मारा है। उनके घरों पर कई कागजों की जांच की गई है और पूछताछ की गई है। इसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जितेंद्र ओझा को अपने साथ ले गई। खबर है कि इस कंपनी के कई कर्मचारियों के घरों में कई जगहों पर जांच शुरू की गई है। इस तलाशी में दो टीमों के आर्टी अधिकारी शामिल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ED आज भी CBI की 2014 की जांच के आधार पर जांच प्रक्रिया जारी रखे हुए है। आदर्श ग्रुप के हेड बताए जाने वाले विजय राउत को उस समय चिटफंड के पैसे में गड़बड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

नरसिम्हा मिश्रा ने कांग्रेस पर अपना गुस्सा निकाला और आरोप लगाया कि वह उन्हें नजरअंदाज कर रही है!

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओडिशा

भूबनेश्वर : कांग्रेस के सीनियर नेता नरसिंह मिश्रा का विस्फोटक बयान। नरसिंह मिश्रा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें नजरअंदाज कर रही है। पिछले आम चुनावों के बाद से उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है और पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें फोन कॉल भी नहीं आ रहे हैं। पहले कानून मंत्री, विपक्ष के नेता, कांग्रेस MLA और लेजिस्लेटिव काउंसिलर के सदस्य होने थे। उस समय पार्टी उनसे जरूरी फ्रैसले लेती थी। लेकिन भक्त दास के PCC प्रेसिडेंट बनने के बाद पार्टी ने उनसे नहीं पूछा, नरसिम्हा ने कहा। पिछले नुआपाडा उपचुनाव में उन्हें नहीं बुलाया गया था। उन्होंने साफ़ किया कि वे पार्टी नहीं छोड़ेंगे।

बीजेपी को नकारात्मक नहीं विकास की राजनीति सिखनी चाहिए, डा0 इरफान अंसारी की नसीहत

झारखंड का भविष्य सुरक्षित हाथों में है : मंत्री इरफान कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

राची, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने प्रेस बयान जारी कर कहा है कि महागठबंधन सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में अब तक की सबसे बड़ी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर राज्य के इतिहास में नया अध्याय लिखा है। सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर मोरहाबादी मैदान, रांची में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री ने 8,792 नव-नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इसके साथ ही 8,000 से अधिक युवाओं को सरकारी, जबकि 8,500 युवाओं को गैर-सरकारी क्षेत्र में रोजगार मिला है। मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि सरकार ने साबित कर दिया है कि झारखंड का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी को नकारात्मक राजनीति छोड़कर काम और विकास की राजनीति से सीख लेनी चाहिए। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का भी सकारात्मक असर दिखा है। कई गरीब बेटियों ने बताया कि मई-जून सम्मान योजना की मदद से वे पढ़-लिखकर आज जेपीएससी पास कर चुकीं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती देने के लिए 22 डेंटल डॉक्टरों को भी नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए, जिससे प्राथमिक और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। स्थापना दिवस पर जनता का उत्साह रिकॉर्ड रहा और राज्य सरकार को व्यापक समर्थन मिला। यह अवसर झारखंड की प्रगति और युवा सशक्तिकरण का प्रतीक साबित हुआ।



सरकार का कहना है कि महिलाओं पर अत्याचार कोई जरूरी मुद्दा नहीं है

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओडिशा

भूबनेश्वर : राज्य में रेप, गैंग रेप, सेक्सुअल हैरेसमेंट, हॉस्टल में नाबालिगों का प्रेनेट होना और घर में हुए अत्याचार जैसे कई अत्याचार खतरनाक दर से फैल रहे हैं। स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। यह बात जगजाहिर है कि सरकार, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को इस मुद्दे की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को तरफ से कांग्रेस भवन में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर सरकार से कई मांगों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की प्रवक्ता डॉ. मनीषा दास पटनायक और जयश्री पात्रा ने हिस्सा लिया और महिलाओं की इज्जत के प्रति सरकार के रवैये की कड़ी भाषा में आलोचना करते हुए कई मांगें रखीं।

प्रवक्ता डॉ. दास पटनायक ने कहा कि, ओडिशा में BJP सरकार के 17वें महीने में महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ अत्याचार, रेप, गैंग रेप और हिंसा में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी के बावजूद, ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन के पूरी तरह चुप और इनएक्टिव रहने की कड़ी निंदा करती है। सरकार ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर आंखें मूंद ली हैं। खोरधा बाघमारी में एक नाबालिग लड़की के साथ बेरमी से गैंगरेप के बावजूद, अपराधी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, मलकानगिरी में 45 साल के आदमी द्वारा 5-7 साल की

तीन नाबालिग लड़कियों के साथ अमानवीय बलात्कार की धीमी जांच, और कटक SCB मेडिकल कॉलेज के ICU में एक महिला के साथ दिल दहला देने वाला दुर्व्यवहार - ये सभी घटनाएं राज्य के कानून के शासन की अक्षमता, लापरवाही और टूटने को साफ तौर पर दिखाती हैं। पूरी, ब्योझर, मयूरभंज, संबलपुर, गोपालपुर और रायगडा में लगभग हर हफ्ते महिलाओं के खिलाफ हिंसा की नई घटनाएं होने के बावजूद, सरकार कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे में, ओडिशा प्रदेश महिला कांग्रेस तुरंत फास्ट-ट्रैक ट्रायल, एक विशेष महिला जांच टीम बनाने, निम्मेदार पुलिस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीड़ितों को सुरक्षा-परामर्श-कानूनी मदद देने की मांग कर रही है। इस गंभीर स्थिति में, डॉ. दास पटनायक ने फिर कहा कि महिलाओं की सुरक्षा राजनीति का विषय नहीं है, यह सरकार का मूल कर्तव्य है, अगर ऐसी ही निष्क्रियता जारी रहती, तो ओडिशा की महिलाएं कभी चुप नहीं रहेंगी और सड़कों पर लड़ाई जारी रहेगी, उन्होंने कहा। सम्मेलन की प्रवक्ताओं में से एक, श्रीमती पात्रा ने कहा, खोरधा जिले के बाघमारी इलाके में एक दलित नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, मलकानगिरी में 3 बच्चों के साथ रेप हुआ, नीमापारा में एक नाबालिग लड़की लापता हो गई, राज्य में क्या चल रहा है, श्रीमती जयश्री पात्रा ने पूछा। डबल इंजन सरकार में,

महिलाएं दोगुनी असुरक्षित हैं। 17 महीने की सरकार में, 10,000 महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, 3,377 महिलाओं को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, 2,465 महिलाओं ने आत्महत्या की, 3,178 महिलाओं को किडनैप किया गया, और 10 महीनों में 2,44 की हत्या कर दी गई। उन्होंने पूछा कि अच्छे शासन का रॉडिंडम कैसे पीटा जा रहा है। रबेटी बचाओ बेटा पढ़ाओ एक सफेद झूठ है, परदे के पीछे सच छिपाने की कोशिश है। राज्य में महिला डिप्टी चीफ मिनिस्टर और महिला स्पीकर होने के बावजूद, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई तैयारी नहीं है। नही लोगों की सरकार में कोई एक्शन या ईमानदारी है। खोरधा इलाके के MLA ने भुवनेश्वर के MPs की ऐसी घटनाओं में शामिल न होने और खाकी वर्दी नेताओं की असंवेदनशीलता की आलोचना की है। आम लोगों को कौन पूछ रहा है, स्पोकसपर्सन, श्रीमती जयश्री पात्रा ने पूछा। खाकी वर्दी की तैयारी और एक्शन की कमी के कारण महिलाएं ज्यादा परेशान और असुरक्षित हैं। पीड़िता की मां ने कहा कि यह बहुत निंदनीय है कि पुलिस मुख्य आरोपी को केस से बरी करने के लिए दबाव डाल रही है।

हाईवे से लेकर असेंबली तक, महिलाएं अपनी सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों के लिए लड़ेंगी और मजबूत होंगी, सरकार को चेतावनी दी, श्रीमती पात्रा ने।

FICCI FLO अमृतसर का “डिकोड योर डेस्टिनी” कार्यक्रम, जीवन संतुलन और सेवा का मिला संदेश



अमृतसर, 28 नवंबर (साहिल बेरी)

FICCI FLO अमृतसर की ओर से ताज स्वरना में शुक्रवार को “डिकोड योर डेस्टिनी” कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चेयरपर्सन मोना सिंह ने की। इसमें मशहूर ज्योतिष, वास्तु और वेलेनेस विशेषज्ञ डॉ. जय मदान ने विशेष सत्र लिया। करीब 200 सदस्यों की उपस्थिति के साथ यह कार्यक्रम आत्म-विकास और सकारात्मक सोच को समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हुआ। कार्यक्रम के दौरान एक पैनाल चर्चा भी हुई, जिसमें मोना सिंह, डॉ. जय मदान और डेमेटोलॉजिस्ट एवं एस्थेटिक विशेषज्ञ डॉ. जसलीन ने

भाग लिया। चर्चा में भावनात्मक संतुलन, अंतर-ज्ञान की भूमिका और रोजमर्रा के जीवन पर प्रभाव डालने वाली सूक्ष्म ऊर्जा पर विस्तार से बात की गई। विशेषज्ञों ने बताया कि ऊर्जाओं का सही संतुलन व्यक्ति के व्यवहार और निर्णयों को कैसे दिशा देता है। शाम का मुख्य आकर्षण डॉ. जय मदान का स्वतंत्र सत्र रहा। उन्होंने सदस्यों को समझाया कि मन और वातावरण की हल्की ऊर्जा गड़बड़ी के कारण कई बार बेचैनी क्यों महसूस होती है। उन्होंने छोटे-छोटे सुधारात्मक कदमों के माध्यम से जीवन में संतुलन लाने के सरल उपाय भी साझा किए। प्राचीन

भारतीय ज्ञान को आधुनिक जीवनशैली से जोड़ते हुए उनके विचारों ने उपस्थित दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। अमृतसर ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए वंचित परिवारों की स्कूलों बालिकाओं को 15 साइकिलें भेंट कीं। यह पहल मुकुल माधव फाउंडेशन और फिनोलेक्स के सहयोग से संभव हुई। संगठन ने राष्ट्रीय पहल प्रमुख श्रीमती रितु छाबड़िया का निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद भी किया। कार्यक्रम ने व्यक्तिगत प्रगति और सामाजिक सरोकार दोनों को मजबूत करने का संदेश दिया।